

(17) चूंकि मुआवजे की राशि अदालत में जमा की गई है, इसलिए ब्याज के साथ-साथ प्रति वर्ष @६% के साथ समान राशि के बराबर राशि का आरोप उक्त राशि पर बनाया गया है जब तक कि ज़मींदारों को देयता स्पष्ट नहीं है, बहुत कम, बयाना को वापस कर दें आदेश के रूप में धन और उसी को हटा दिया जाएगा, जिस क्षण भूस्वामियों ने अपनी देयता का निर्वहन किया।

(18) यह स्पष्ट किया गया है कि यदि भूस्वामियों ने पहले से ही मुआवजे की राशि वापस ले ली है, तो अपीलकर्ता कानून के अनुसार इस आदेश के निष्पादन की तलाश करने के हकदार होंगे।

(19) अपील की अनुमति दी गई है और संदर्भ न्यायालय के लगाए गए पुरस्कारों को अलग-अलग सेट किया गया है। तदनुसार डिक्री-शीट तैयार की जाती हैं।

पी.एस.बजवा

एस.एस. सरोन और एस.पी. बंगारह से पहले, जेजे।

इंद्रजीत सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब राज्य

2012 का CRM नंबर M-13140

31 जनवरी, 2014

नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 - एसएस। 2 (xiv), (xi) & (xxiii), 21 और 22-ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940-एसएस। 8, 16, 17, 17 ए, 17 बी, 18 और 27-ड्रग और सौंदर्य प्रसाधन नियम, 1945-नियम 59 (1), 60, 61, 62 ए, 62 बी, 62 सी, 97, 104, 104 ए और 105-नशीले पदार्थों की दवाएं और साइकोट्रोपिक पदार्थ नियम - री। 65 और 65 ए-नोटिफिकेशन एस.ओ. 826 (ई) दिनांक 14-11-1985 और अधिसूचना दिनांक 29-1-1993-अभियुक्त एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2 (xi) के संदर्भ में 'निर्मित दवाओं' के कब्जे में पाया गया था, लेकिन इनमें एक अपवाद के रूप में एक अपवाद था। ड्रग-प्रश्न में खुराक यह पैदा हो गया कि क्या एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक आरोपी को अपराध के लिए कोशिश की जा सकती है-याचिकाकर्ता का मामला यह था कि उसे केवल डी एंड सी अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है कि एनडीपीएस अधिनियम के उल्लंघन में निर्मित दवाओं के कब्जे में अपराधी के आपराधिक अभियोजन को पूरा करेगा। एनडीपीएस एक्ट-ड्रग्स के कड़े प्रावधानों के तहत जो 'निर्मित दवाओं' के तहत कवर किए जाते हैं।

एनडीपीएस अधिनियम और डी एंड सी अधिनियम द्वारा भी कवर किया गया है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि अपराधी को केवल डी एंड सी अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है-इसे प्रत्येक मामले में पता लगाया जाना है कि क्या निर्मित दवा में दवा के लिए प्रदान की गई खुराक के प्रतिशत की अनुमेय सीमाएं हैं।

पर आयोजित-

(i) निर्मित ड्रग्स वे दवाएं हैं जिन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा **2 (xi)** में परिभाषित किया गया है और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। एनडीपीएस अधिनियम और एनडीपीएस नियमों के उल्लंघन में इस तरह की दवाओं का कब्जा एनडीपीएस अधिनियम की धारा **21** के तहत अपराधी के आपराधिक अभियोजन को लागू करेगा।

(ii) केवल तथ्य यह है कि ड्रग्स जो एनडीपीएस अधिनियम और एनडीपीएस नियमों और साइकोट्रोपिक पदार्थों के तहत निर्मित दवाओं के तहत कवर किए जाते हैं, जैसा कि एनडीपीएस अधिनियम और एनडीपीएस नियमों के अनुसूची **1** की अनुसूची में उल्लेख किया गया है और डी एंड सी द्वारा भी कवर किया गया है। अधिनियम और **1945** के नियमों का मतलब यह नहीं होगा कि अपराधी को केवल डी एंड सी अधिनियम और **1945** के नियमों के तहत दंडित किया जा सकता है और एनडीपीएस अधिनियम और एनडीपीएस नियमों के खिलाफ आगे नहीं बढ़ा। यदि एनडीपीएस अधिनियम और एनडीपीएस नियमों का एक उल्लंघन होता है, तो बाद के कड़े प्रावधानों का सहारा लिया जा सकता है।

(iii) एनडीपीएस अधिनियम और एनडीपीएस नियमों के संदर्भ में एक व्यक्ति का निर्माण ड्रग्स और एनडीपीएस नियमों के लिए सख्ती से बिक्री, खरीद, परिवहन, वहन, भंडारण, वितरण आदि से संबंधित प्रावधानों का पालन करना है। **1945** के नियम पंजाब एनडीपीएस नियम **2012** के प्रावधानों के रूप में भी।

(iv) निर्मित दवाओं के परिवहन के लिए पंजाब एनडीपीएस नियम 2012 के नियम 18 के तहत पास या परमिट होना चाहिए।

(v) प्रत्येक मामले में यह पता लगाना है कि क्या निर्मित दवा, जिसका उल्लंघन किया गया है ।

एक व्यक्ति द्वारा 14-11-1985 दिनांकित अधिसूचना द्वारा दवा के लिए प्रदान की गई खुराक के प्रतिशत की अनुमेय सीमा के भीतर और बाद में अधिसूचना दिनांक 29-1-1993 द्वारा धारा 2 (xi) द्वारा प्रदान की गई शक्ति के अभ्यास में जारी की गई है (बी) (बी) एनडीपीएस अधिनियम। हालांकि, निर्मित दवा के उल्लंघन या थोक में मात्रा के कब्जे को ध्यान में रखा जाना है और विशेष रूप से प्रति खुराक के अनुसार जब डी एंड सी अधिनियम और 1945 के नियमों का उल्लंघन होता है, जो कहना है कि उन्हें बेचा, खरीदा, वितरित किया गया है, संग्रहीत किया गया है, एक वैध लाइसेंस के बिना या एक वैध प्राधिकरण के बिना रखा गया, ले जाया गया। थोक में मात्रा का कब्जा एक संकेत होगा कि यह औषधीय या चिकित्सीय उपयोग के लिए नहीं है, लेकिन ड्रग के नशे की लत और ड्रग तस्करों द्वारा दुरुपयोग किए जाने की मांग की जाती है और किसी को भी या अधिक मादक दवा या साइकोट्रोपिक के लिए लागू होने के लिए लागू किया जाएगा। खुराक रूपों में उस विशेष दवा का पदार्थ न कि केवल इसकी शुद्ध दवा सामग्री।

(पैरा ५६)

जे.एस. 2012 के सीआरएम नंबर एम -13140 में याचिकाकर्ता के लिए अरोड़ा, एडवोकेट।

पिताशय 2013 के CRM नंबर M-1379 में याचिकाकर्ता के लिए AHLUWALIA, एडवोकेट।

शशिकांत गुप्ता, एल.एम. गुलाटी के लिए वकील, 2012 के सीआरएम नंबर एम -14461 में याचिकाकर्ता के लिए वकील।

पिताशय 2012 के सीआरएम नंबर एम -20282 में याचिकाकर्ता के लिए सेखोन, अधिवक्ता।

डी.एस. फेरुमन, एडवोकेट, आर.के. गुप्ता, अधिवक्ता, परवीन कटारिया, अधिवक्ता और अक्षय जैन, वकील के रूप में अंतराल।

Pps thetti, addII ए.जी., पंजाब में सीआरएल। विविध। 2012 के NosI M-13140, 14461 और 20282।

एस.एस. धालीवाल, AddII A.G., 2013 के CRM नंबर M-1379 में पंजाब।

एस.एस. सरोन, जे।

(1) यह आदेश इंद्रजीत सिंह @laddi बनाम पंजाब CRM No. M- 13140 के राज्य में सीखे गए एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए संदर्भों का निपटान करेगा; रविंदर सिंह @ रिकू बनाम। पंजाब सीआरएम नंबर एम -1379 ऑफ 2013 का राज्य; 2012 के रानी बनाम पंजाब सीआरएम नंबर एम - 14461 और मोहम्मद। शमशाद बनाम 2012 के पंजाब सीआरएम नंबर एम -20282 राज्य।

। "- छोटे के लिए):-

(ए) ३० रेक्सोफ़ बोतलें ५.88 ग्राम कोडीन युक्त हैं।

(बी) 1500 मोमोलिट ऑफ़ टैबलेट्स जिसमें 3.45 ग्राम डिपेनोक्सिलेट है।

(c) 500 फेनोटिल की गोलियाँ जिसमें 1.1 gms diphenoxylate होता है।

(डी) 150 पार्वान स्पास कैप्सूल में 9.70 ग्राम डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफीन होते हैं।

(३) यह याचिकाकर्ता की ओर से बालजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (१) और मंजित सिंह बनाम पंजाब राज्य (२) में इस अदालत के दो निर्णयों के बल पर चुनाव लिया गया है। 'निर्मित ड्रग्स' होने के नाते नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 ("एनडीपीएस अधिनियम" - संक्षेप में) के दायरे में नहीं आते हैं और याचिकाकर्ता को सबसे अच्छा मुकदमा चलाया जा सकता है और अपराधों के लिए प्रयास किया जा सकता है, यदि

कोई हो, तो ड्रग्स के नीचे और कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 ("डी एंड सी एक्ट" - शॉर्ट के लिए)।

(४) राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता से बरामद किए गए पदार्थ या जिनके संबंध में एक उल्लंघन किया गया है, धारा 2 (xi) एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा कवर किए गए 'निर्मित ड्रग्स' हैं। एफएसएल रिपोर्ट, एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए उनके अभियोजन और परीक्षण में बनाए रखने योग्य है।

(१) २००३ (१) cri.cc ४

(२) २०११ (१) आरसीआर (cri I) ९० (

(५) प्रतिद्वंद्वी सामग्री पर विचार करने के बाद सीखा एकल न्यायाधीश ने पाया कि इस सवाल का सवाल है कि क्या इस तरह के पदार्थ/ड्रग्स एनडीपीएस अधिनियम के तहत कवर किए गए हैं या नहीं, या केवल डी एंड सी अधिनियम के तहत निपटा जा सकता है, कई मामलों में अक्सर उत्पन्न हो रहा है। परिणाम पूरी तरह से अलग होंगे यदि पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के बजाय डी एंड सी अधिनियम के दायरे में होने के लिए आयोजित किए गए थे। इसलिए, मामला एक बड़ी पीठ के लिए संदर्भित किया गया था। इस बीच, याचिकाकर्ता को सीखा ट्रायल कोर्ट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ड्यूटी मजिस्ट्रेट, लुधियाना की संतुष्टि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था।

। रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट (एनेक्सोर पी -2) के बाद रासायनिक परीक्षा के बाद विभिन्न अवयवों के साथ-साथ रिकवरी में पाए गए मात्रा के साथ-साथ विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित किया गया था:-

डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफेन एचसीएल।

सकारात्मक

डाइसाइक्लोमाइन एचसीएल

सकारात्मक

एसिटामिनोफेन

सकारात्मक

एवीजी। Wt।

0.648 ग्राम

एवीजी। शुद्ध सामग्री

0.496 ग्राम

के लिए परख -

डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफेन एचसीएल।

61.986 मिलीग्राम/कैप

एसिटामिनोफेन

381.76 मिलीग्राम/कैप

डाइसाइक्लोमाइन एचसीएल

9.535 मिलीग्राम/कैप।

(०) रासायनिक परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विश्लेषक द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार, नमूनों में डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफेन एचसीएल, एसिटामिनोफेन, डाइस्लिक्लोमिन हेल में शामिल हैं। रासायनिक परीक्षक

446I.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (1)

रिपोर्ट (अनुलग्नक पी -3) में, परीक्षा सफेद रंग के गोल प्लैट के संबंध में आयोजित की गई थी, जो एक तरफ माइक्रोन के साथ अंकित और ढीले पॉलीथीन पाउच में अन्य पैक की गई सादे सतह के साथ खुदा हुई थी। संदर्भ के तहत पार्सल की सामग्री को रासायनिक विश्लेषण और पर अलग से विश्लेषण किया गया था।

विश्लेषण के आधार पर, इन में मौजूद मात्रा के साथ विभिन्न अवयवों को विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार वर्णित किया गया था:-

डिपेनोक्सिलेट एचसीएल।

सकारात्मक

एवीजी। Wt।

0.0741 ग्राम

के लिए परख -

डिपेनोक्सिलेट एचसीएल।

2.445 मिलीग्राम/टैब

(8) विश्लेषक द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार नमूना में डिपेनोक्सिलेट एचसीएल था।

(xi) एनडीपीएस अधिनियम का। 'निर्मित दवा' की परिभाषा यह बताई गई है कि केंद्र सरकार किसी भी मादक पदार्थ को धारा 2 (xi) एनडीपीएस अधिनियम के अनुसरण में निर्मित दवा होने के लिए सूचित कर सकती है। यह है कि वित्त मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे भारत

के गजट, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप खंड (ii) में 14.11.1985 में प्रकाशित किया गया था, जिससे कुछ मादक पदार्थों और तैयारी को निर्मित घोषित किया गया था ड्रग्स। याचिकाकर्ता रविंदर सिंह उर्फ रिकू के अनुसार, उक्त अधिसूचना का एक अवलोकन यह दर्शाता है कि डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफीन और डिपेनोक्सिलेट को निर्मित ड्रग्स घोषित किया गया है और उनका कब्जा धारा 21 के दायरे में होगा और न कि धारा 22 एनडीपीएस अधिनियम। यह प्रस्तुत किया गया है कि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्टें (अनुलग्नक पी 2 और एनेक्सोर पी 3) की स्थिति से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता राविंदर सिंह उर्फ रिकू से बरामद की गई दवाओं में डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफीन की मात्रा 61.986 मिलीग्राम/कैप्सूल है, जो 135 से कम है, जो 135 से कम है, जो 135 से कम है। एमजी और इसलिए भारत के सरकार द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त अधिसूचना में प्रदान किए गए अपवाद के भीतर आएगा। इसी तरह, याचिकाकर्ता के उदाहरण पर दर्ज की गई दवा में डिपेनोक्सिलेट की मात्रा 2.445 मिलीग्राम/टैबलेट है जो उक्त अधिसूचना के तहत अपवाद के भीतर भी आता है। सीखा एकल न्यायाधीश ने 2012 के CRM नंबर M-13140 के साथ एक डिवीजन बेंच के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

(10) रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, पार्वान स्प्रास कैप्सूल जो बरामद किए गए थे, उनमें नमक डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफीन एचसीएल 74.90 मिलीग्राम और कैप्सूल में समरूपता में डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफीन एचसीएल 74.96 मिलीग्राम का नमक शामिल था। यह उसकी ओर से किया गया था कि अगर उपरोक्त की गणना ने डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफीन एचसीएल के नमक का प्रतिशत कहा। जिसे 74.90 मिलीग्राम माना जाता है, कथित वसूली गैर-वाणिज्यिक के दायरे में है। सीखा एकल न्यायाधीश ने 2012 के सीआरएम नंबर एम -13140 में पारित आदेश के मद्देनजर मामले को एक बड़ी बेंच के लिए संदर्भित किया।

(११) मोहम्मद में। शमशाद बनाम पंजाब राज्य (2012 का CRM नंबर M-20282), याचिकाकर्ता गांव रुर्की कलान, तहसील माल्कोटला, जिला संगरूर में स्थित मेसर्स भारत मेडिकल हॉल के नाम पर एक रसायनज्ञ की दुकान चला रहा था। उनके पास एक वैध लाइसेंस नंबर 22983 दिनांक 12.12.2006 था जो 11.12.2011 तक मान्य था। 9.12.2011 को, उक्त याचिकाकर्ता ने नवीकरण शुल्क प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार किया गया था। हालांकि, नया लाइसेंस जारी नहीं किया गया था। अभियोजन मामले के अनुसार, पार्वान स्प्रा के 500 कैप्सूल उक्त याचिकाकर्ता से बरामद किए गए थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, वही एनडीपीएस अधिनियम के दायरे में नहीं आता है। जो दवा बरामद की गई है, उसे प्रस्तुत किया गया है, इसमें पेरसिटामोल डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफीन हाइड्रोक्लोराइड और डाइसीक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड शामिल हैं। मादक दवाओं और साइकोट्रॉपिक पदार्थों की सूची में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता मोहम्मद के अनुसार। शमशाद एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं किया जाता है

इस मामले में बाहर। (१२) एफिडेविट श के माध्यम से दायर उत्तर में। बिमल कुमार पीपीएस, पुलिस उप अधीक्षक, सब डिवीजन, माल्कोटला, मोहम्मद में जिला संगरूर। शमसाद के मामले (सुप्रा) यह कहा गया है कि हालांकि याचिकाकर्ता के पास एक लाइसेंस है, हालांकि, उसे खुले सार्वजनिक स्थान पर नशीले पदार्थों को बेचने का कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता मोहम्मद के कब्जे से तरल नशीले पदार्थों की दो बोतलें और पार्वान स्प्रा के 500 कैप्सूल बरामद किए गए थे। कुटी रोड मंदिर के क्षेत्र में शमसाद, माल्कोटला के अधिकार क्षेत्र में माल्कोटला। सहायक निदेशक (विष विज्ञान), एफएसएल,

INDERJEET SINGH v. पंजाब की स्थिति (एस.एस. सरोन, 1)449
पंजाब की 3.10.2012 की रिपोर्ट के संदर्भ में, बरामद तरल नशीले पदार्थों की
सामग्री थी।

कोडीन फॉस्फेट 5.6 मिलीग्राम/5 एमएल होने की सूचना दी और कैप्सूल को डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफीन हाइड्रोक्लोराइड 64.8 मिलीग्राम/कैप्सूल होने की सूचना दी गई और इन लवणों का उल्लेख उप-क्लॉस (वीआईआईए) और (एक्सएक्सआईआईए) में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2 से सीरियल नाओ 28 पर किया गया है। और एनडीपीएस अधिनियम में छोटी मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा को निर्दिष्ट करने वाली तालिका में क्रमशः 33 केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 19.10.2001 द्वारा जारी की गई है। रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट को एनेक्सोर आर -1 के रूप में संलग्न किया गया है। सीखा एकल न्यायाधीश ने मामले को 2012 के CRM नंबर M-13140 के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया और इस बीच, याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।

(१३) दिनांक ६.९.२०१२ के आदेश का एक विद्रोह इंद्रजीत सिंह @ लड्डी (सुप्रा) के मामले में पारित किया गया था कि यह याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील द्वारा उक्त मामले में कहा गया था कि "निर्मित दवाएं" के भीतर नहीं आती हैं एनडीपीएस अधिनियम और याचिकाकर्ता के दायरे में केवल ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम के तहत सबसे अधिक मुकदमा चलाया जा सकता है और एनडीपीएस अधिनियम के तहत नहीं। किसी भी मामले में उन पर केवल धारा 21 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत नहीं।

(१४) याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित होने वाले वकील ने अंतर किया है मुख्य रूप से एक अभियुक्त से वसूली के संबंध में कहा गया है। निर्मित दवाओं का सम्मान, एक अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत। यह इस कारण से अधिक है कि कुछ निश्चित है। 'निर्मित दवाओं' को अधिसूचना द्वारा 'मादक दवाएं' घोषित किया गया था। केंद्र सरकार की सूचना दिनांक 14.11.1985 में 88 ड्रग्स को 'मादक दवाएं' घोषित किया गया था, इसके अलावा, नोटिफिकेशन दिनांक 29.1.1993, 17 और दवाओं को 'निर्मित दवाओं' के रूप में सूचित किया गया था। हालांकि, इन सूचनाओं में विभिन्न अपवाद हैं और मामले में 'निर्मित दवा' जिसके संबंध में उल्लंघन का आरोप है लेकिन जो अपवादों के भीतर आता है तब मामला भीतर नहीं आएगा एनडीपीएस अधिनियम का दायरा। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि दवाएं अधिसूचनाओं में

कौन से अपवाद बनाए गए हैं, इसके संबंध में- कहा, एक अभियोजन को एनडीपीएस अधिनियम के तहत लॉन्च नहीं किया जा सकता है। यह है ड्रग्स और सौंदर्य प्रसाधन नियमों के नियम 97 के संदर्भ में प्रस्तुत किया 1945 ("1945 नियम" - शॉर्ट के लिए), दवाओं का लेबलिंग किया जाना है। दवा की सामग्री और अनुसूची के अनुसार जिसके तहत

जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया है। यदि 1945 के नियमों के अनुसूची 'एच' में उल्लिखित कोई भी दवा बिना लेबलिंग के पाई जाती है, तो डी एंड सी अधिनियम और 1945 के नियमों के तहत केवल सबसे अधिक उत्तरदायी होने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति 1945 के नियमों के अनुसूची 'एच' में उल्लिखित किसी भी दवा के कब्जे में पाया जाता है, साथ ही साथ दिनांक 4.11.1985 और 29.1.1993 की सूचनाएं, जो उस अपवाद के किसी भी अपवाद के भीतर आती हैं, तो ये केवल D & C अधिनियम के तहत आजमाने के लिए उत्तरदायी हैं। यह, यह प्रस्तुत किया गया है, D & C अधिनियम और नियम 97, 104, 104-A और 105 के 1945 के नियमों के लिए धारा 16, 17, 17-A, 17-B और 18 पढ़ने का संयुक्त प्रभाव है, जो मानकों के लिए प्रदान करते हैं D & C अधिनियम के तहत बनाए रखा जाना और उसके उल्लंघन का उल्लंघन D & C अधिनियम की धारा 18 के तहत एक अपराध है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई प्रावधान नहीं है जो उक्त अधिनियम के तहत इस तरह के अपराध के लिए प्रयास करने के लिए निर्धारित करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि किसी भी दवा/साइकोट्रोपिक पदार्थ को किसी भी अनधिकृत व्यक्ति से बरामद किया गया है और इसे मादक दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों के नियम 1985 के अनुसूची 1 द्वारा कवर किया गया है (जैसा कि संशोधित किया गया है) ("एनडीपीएस नियम" - संक्षेप में), तो यह कोशिश की जानी है एनडीपीएस अधिनियम के तहत और यदि इस तरह की दवा और साइकोट्रोपिक पदार्थ एनडीपीएस नियमों के अनुसूची 1 द्वारा कवर नहीं किया जाता है, जैसा कि एनडीपीएस नियमों के नियम 64 के तहत प्रदान किया गया है तो यह कोशिश की जाने वाली है

D & C अधिनियम के तहत। (१५) जवाब में, सीखा राज्य वकील ने प्रस्तुत किया है कि देश के इस हिस्से में ड्रग्स का खतरा इतना बड़ा है कि इसे भारी हाथ से अंकित किया जाना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एनडीपीएस अधिनियम और एनडीपीएस नियमों का प्रावधान, इसके अलावा, डी एंड सी अधिनियम और 1945 के नियमों ने केवल अपराधों को आजमाने के लिए प्रक्रिया प्रदान की है। यह प्रस्तुत किया गया है कि डी एंड सी अधिनियम और 1945 के नियमों के तहत कुछ दवाओं के अतिव्यापी हो सकते हैं, साथ ही एनडीपीएस अधिनियम और एनडीपीएस नियम भी हो सकते हैं, हालांकि, वही असंगत है क्योंकि यह राज्य के लिए कानून के अनुसार अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिए है और यदि NDPS अधिनियम और NDPS नियमों के तहत

एक कठोर प्रावधान दवाओं के संबंध में सहारा लिया जाता है जो NDPS अधिनियम के तहत आते हैं, तो वही शून्य नहीं किया जाना है या परीक्षण को केवल अवैध घोषित किया गया है क्योंकि एक कठोर प्रावधान का पालन किया गया है। किसी भी मामले में यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्मित दवाओं की मात्रा, जिनमें से एक उल्लंघन किया गया है, थोक में लिया जाना है न कि प्रति कैप्सूल दवाओं की खुराक के आधार पर। भले ही आपत्तिजनक दवा की सामग्री अपवाद के भीतर गिरती है, तो पूरे के संबंध में भी यही लिया जाना चाहिए।

जिनमें से एक उल्लंघन हुआ है या अनधिकृत रूप से बरामद किया गया है।

(१६) हमने इस मामले को अपने विचारशील विचार दिए हैं। विचार के लिए जो सवाल उठता है, वह यह है कि क्या किसी अभियुक्त को एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के लिए प्रयास किया जा सकता है, जब वह 'निर्मित दवाओं' के कब्जे में पाया जाता है जो धारा 2 (xi) के संदर्भ में 'निर्मित दवा' की परिभाषा में गिरता है NDPS अधिनियम में से और इस तरह से सूचित किया गया है कि 14.11.1985 और 29.1.1993 को 'निर्मित दवाओं' के रूप में सूचनाओं के अनुसार, लेकिन दवा में खुराक के प्रतिशत के संबंध में एक अपवाद होता है।

(१०) उक्त मुद्दे पर विचार करने के लिए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा २ (xiv), (xi) और (xxiii) में परिभाषित 'मादक दवा,' निर्मित दवा 'और ops साइकोट्रोपिक पदार्थ' की परिभाषाएँ देखी जा सकती हैं जो अंडर के रूप में पढ़ते हैं:-

"(xiv)" मादक दवा "का अर्थ है कोका लीफ, कैनबिस (गांजा), अफीम, अफीम, खसखस है और इसमें सभी निर्मित सामान शामिल हैं; 37

"(xi)" निर्मित दवा "का अर्थ है-

(ए) सभी कोका डेरिवेटिव, औषधीय कैनबिस, अफीम डेरिवेटिव और पोपी पुआल केंद्रित;

(बी) किसी भी अन्य मादक पदार्थ या तैयारी जो केंद्र सरकार, उपलब्ध जानकारी के बारे में उपलब्ध जानकारी के लिए या किसी निर्णय के लिए, यदि कोई हो, किसी भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के तहत, आधिकारिक गजट में अधिसूचना के द्वारा, "एक" एक "घोषित किया जा सकता है," निर्मित दवा: "(जोर जोड़ा)।

(१९) इसलिए, केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, किसी भी अन्य मादक पदार्थ को घोषित कर सकती है या 'निर्मित दवा "होने की तैयारी कर सकती है। उप-

"(XXIII)" साइकोट्रोपिक पदार्थ "का अर्थ है किसी भी पदार्थ, प्राकृतिक या सिंथेटिक, या किसी भी प्राकृतिक सामग्री या किसी भी नमक या ऐसे पदार्थ या सामग्री की तैयारी का अर्थ है, अनुसूची में निर्दिष्ट साइकोट्रोपिक पदार्थों की सूची में शामिल:"

(२०) साइकोट्रोपिक पदार्थ को किसी भी पदार्थ, प्राकृतिक या सिंथेटिक, या किसी भी प्राकृतिक सामग्री या किसी भी नमक या इस तरह के पदार्थ या सामग्री की तैयारी के लिए परिभाषित किया गया है, जो एनडीपीएस अधिनियम के अनुसूची में निर्दिष्ट साइकोट्रोपिक पदार्थों की सूची में शामिल है।

यदि कोई भी, किसी भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के तहत, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक निर्मित दवा घोषित किया जाता है, तो इसे इस तरह माना जाता है, अर्थात्, निर्मित दवा के रूप में। वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, ने अधिसूचना S.O. प्रकाशित किया है। 826 (ई) दिनांक 14.11.1985 भारत के राजपत्र में, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (II)। उक्त अधिसूचना धारा 2 एनडीपीएस अधिनियम के उप खंड (बी) द्वारा प्रदान की गई शक्ति के अभ्यास में जारी की गई है, जिसके संदर्भ में केंद्र सरकार ने मादक पदार्थों और तैयारी को "निर्मित दवा" के रूप में उल्लेख किया है, । वर्तमान मामलों में उल्लिखित दवाओं के रूप में इन्सोफ़र का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि इंद्रजीत सिंह @ लड्डी (2012 के सीआरएम नंबर एम -13140) के मामले में, 30 रेक्सोफ बोतलें जिसमें 5.88 ग्राम कोडीन हैं; Diphenoxylate के 3.45 ग्राम युक्त गोलियों के 1500 मोमोलिट; 500 फेनोटिल की गोलियां जिसमें 1.1 ग्राम डिपेनोक्सिलेट और 150 पार्वान स्पास कैप्सूल होते हैं, जिनमें 9.70 ग्राम डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफीन को बरामद किया गया था। डी एंड .सी एक्ट और 1945 के नियमों के तहत विभिन्न दवाएं प्रदान की जाती हैं, जो एनडीपीएस अधिनियम में भी प्रदान की जाती हैं और इसलिए, कुछ हद तक ओवरलैपिंग है। D & C अधिनियम को 1940 में लागू किया गया था। D & C अधिनियम की दूसरी अनुसूची आयातित दवाओं द्वारा और बिक्री के लिए निर्मित दवाओं द्वारा और बिक्री या वितरित की गई बिक्री के लिए निर्मित दवाओं द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मानकों को

निर्धारित करती है। D & C अधिनियम का अध्याय III 'ड्रग्स और सौंदर्य प्रसाधन के आयात' से संबंधित है। धारा 8 के बारे में 'गुणवत्ता के मानकों' से संबंधित है। यह डी एंड सी अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) के संदर्भ में प्रदान किया गया है।

धारा 2 एनडीपीएस अधिनियम के खंड (XXIII) में विभिन्न साइकोट्रोपिक पदार्थ का उल्लेख है, जिसमें सीरियल नंबर 30 में अल्प्राजोलम, सीरियल नंबर 36 में क्लोर्डियाज़ेपॉक्साइड, सीरियल नंबर 4 पर डेलोराज़ेपम और विभिन्न अन्य, इसके अलावा, नमक और उसमें वर्णित दवाओं की तैयारी शामिल है। । एनडीपीएस नियमों में, अध्याय I//साइकोट्रोपिक पदार्थों से संबंधित है।

(22) एनडीपीएस नियमों के नियम 68, 69 और 70 ए के तहत पढ़ा गया है:- "68। सामान्य निषेध। कोई भी व्यक्ति निर्माण, अधिकार, परिवहन, आयात अंतर-राज्य, निर्यात अंतर-राज्य, बिक्री, खरीद, उपभोग या उपयोग नहीं करेगा। अनुसूची I में निर्दिष्ट कोई भी साइकोट्रोपिक पदार्थ।

65. साइकोट्रोपिक पदार्थों का निर्माण। । इसके बाद 1945 के नियमों के रूप में संदर्भित) ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 (1940 के 23) के तहत फंसाया गया, इस ओर से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य में ड्रग्स कंट्रोल के प्रभारी प्राधिकरण द्वारा:

बशर्ते कि उपरोक्त एक राज्य में दवा नियंत्रण के प्रभारी प्राधिकारी केवल निर्यात के उद्देश्य के लिए अनुसूची III में निर्दिष्ट एक साइकोट्रोपिक पदार्थ के निर्माण के लिए एक लाइसेंस जारी कर सकते हैं;

(2) किसी राज्य में ड्रग्स कंट्रोल के प्रभारी प्राधिकारी (इसके बाद लाइसेंसिंग अथॉरिटी के रूप में संदर्भित) ड्रग्स कंट्रोलर (भारत) से परामर्श करेंगे। देश में - Rule (1) और राज्य में ऐसे मनोवैज्ञानिक पदार्थों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य के बाहर अन्य निर्माताओं को आपूर्ति के लिए आवश्यक पदार्थ की मात्रा और उचित इन्वेंट्री के लिए आवश्यक पदार्थ की मात्रा की मात्रा के लिए आवश्यक है। एक निर्माता, निर्दिष्ट करेगा, आदेश द्वारा, ऐसे पदार्थ की मात्रा की सीमा जो राज्य में निर्माता द्वारा निर्मित हो सकती है।

(३) उक्त साइकोट्रोपिक पदार्थ की मात्रा जो एक लाइसेंसधारी द्वारा एक वर्ष में निर्मित की जा सकती है, लाइसेंस जारी करने के समय लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंसधारी प्राधिकरण द्वारा सूचित किया जाएगा:

बशर्ते कि इस नियम में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा यदि अनुसूची 1 में निर्दिष्ट साइकोट्रोपिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, परिवहन किया जाता है, परिवहन किया जाता है, आयातित अंतर-राज्य, निर्यात किए गए अंतर-राज्य, बेचा, खरीदे, उपभोग किया जाता है या इस अध्याय के अन्य प्रावधानों के अधीन उपयोग किया जाता है। साइकोट्रोपिक पदार्थों पर लागू होता है जो अनुसूची 1 में और अध्याय VIII A में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए शामिल नहीं हैं:

आगे बशर्ते कि नियम 65 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट राज्य में दवा नियंत्रण के प्रभारी प्राधिकारी ने अनुसूची 1 और अनुसूची में शामिल साइकोट्रोपिक पदार्थों के संबंध में नियम 65 के तहत लाइसेंस जारी करने से पहले नशीले पदार्थों के आयुक्त से परामर्श किया होगा। ///

65 ए। साइकोट्रोपिक पदार्थों की बिक्री, खरीद, खपत या उपयोग। कोई भी व्यक्ति दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन नियमों के अनुसार, किसी भी साइकोट्रोपिक पदार्थ को खरीद, खरीद, उपभोग या उपयोग नहीं करेगा, 1945। "

(२३) एनडीपीएस नियमों के नियम ६४ के संदर्भ में, कोई भी व्यक्ति निर्माण, अधिकार, परिवहन, आयात अंतर-राज्य, निर्यात अंतर-राज्य, बिक्री, खरीद, उपभोग करना, उपभोग करना या उपयोग करना नहीं है। एनडीपीएस नियम। नियम 65 साइकोट्रोपिक पदार्थों के निर्माण से संबंधित है और यह उप-नियम (1) में प्रदान किया गया है कि एनडीपीएस नियमों के अनुसूची 1 में निर्दिष्ट लोगों के अलावा किसी भी साइकोट्रोपिक पदार्थों का निर्माण एक लाइसेंस की शर्तों के अनुसार होगा। 1945 के नियम, इस ओर से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य में ड्रग्स कंट्रोल के प्रभारी प्राधिकरण द्वारा। एनडीपीएस नियमों के नियम 65 के उप-नियम (2) के संदर्भ में, एक राज्य में

ड्रग्स कंट्रोल के प्रभारी प्राधिकरण जो कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण है, प्रत्येक की मूल्यांकन की गई वार्षिक आवश्यकताओं के संबंध में ड्रग्स कंट्रोलर (भारत) से परामर्श करना है देश में उप-नियम (1) में संदर्भित थोक रूप में साइकोट्रोपिक पदार्थों को और राज्य में ऐसे मनोवैज्ञानिक पदार्थों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए,

राज्य के बाहर अन्य निर्माताओं को आपूर्ति के लिए आवश्यक ऐसे पदार्थ की मात्रा और एक निर्माता द्वारा आयोजित किए जाने वाले उचित इन्वेंट्री के लिए आवश्यक ऐसे पदार्थ की मात्रा, आदेश द्वारा निर्दिष्ट करेगी, ऐसे पदार्थ की मात्रा की सीमा जो द्वारा निर्मित की जा सकती है राज्य में निर्माता। एनडीपीएस नियमों के नियम 65 ए के संदर्भ में, कोई भी व्यक्ति 1945 के नियमों के अनुसार, साइकोट्रोपिक पदार्थ को बेचने, खरीदने, उपभोग करने या उपयोग करने के लिए नहीं है। नियम 64 में संदर्भित एनडीपीएस नियमों का अनुसूची। विभिन्न मादक दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों के लिए प्रदान करता है। एनडीपीएस अधिनियम और एनडीपीएस नियमों के प्रावधानों के रूप में डी एंड सी अधिनियम और 1945 के नियमों से पता चलता है कि विभिन्न प्रकार की दवाओं का अतिव्यापी है।

(24) 14.11.1985 दिनांकित पूर्व-संदर्भित अधिसूचना के संदर्भ में, 88 दवाओं को सूचित किया गया है और 10 दवाएं कुछ प्रकार के अपवादों के लिए प्रदान करती हैं, जिनका उल्लेख सीरियल नोस 16, 35, 36, 37, 48, 58 में किया गया है।, 70, 76, 83 और 87 जो अंडर के रूप में पढ़ते हैं:-

"(16) भारतीय गांजा के अर्क या टिंचर से की गई तैयारी, सिवाय उन लोगों को छोड़कर जो केवल बाहरी उपयोग के लिए सक्षम हैं।

(35) मिथाइल मॉर्फिन (आमतौर पर 'कोडीन' के रूप में जाना जाता है) और एथिल मॉर्फिन और उनके लवण (डायोनिन सहित), सभी dilutions और तैयारी, उन लोगों को छोड़कर जो एक या अधिक अन्य अवयवों के साथ जटिल हैं और दवा के 100 मिलीग्राम से अधिक नहीं हैं /प्रति खुराक इकाई और अविभाजित तैयारी में 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं की एकाग्रता के साथ और जो चिकित्सीय अभ्यास में स्थापित किया गया है।

। ड्रग प्रति खुराक इकाई और अविभाजित तैयारी में 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं की एकाग्रता के साथ और जो चिकित्सीय अभ्यास में स्थापित किया गया है।

(37) बीटा -4 - मर्फिलिनिलिथाइलमॉर्फिन (जिसे होमोकोडीन, हाइबरनिल, फोलकोडिन और इस तरह भी जाना जाता है) और इसके लवण:

और *dilutions* और तैयारी, उन लोगों को छोड़कर जो एक या अधिक अन्य अवयवों के साथ जटिल होते हैं और अधिक नहीं होते हैं, फिर प्रति खुराक इकाई में दवा के 100 मिलीग्राम और अविभाजित तैयारी में 2.5 प्रतिशत से अधिक की एकाग्रता के साथ और जो चिकित्सीय में स्थापित किए गए हैं। अभ्यास।

(48) नॉरकोडीन और इसके लवण; सभी *dilutions* और तैयारी, उन लोगों को छोड़कर जो एक या अधिक अन्य अवयवों के साथ जटिल होते हैं और प्रति खुराक इकाई में 100 मिलीग्राम से अधिक दवा नहीं होती है और अविभाजित तैयारी में 2.5 प्रतिशत से अधिक की एकाग्रता नहीं होती है और जो चिकित्सीय अभ्यास में स्थापित की गई हैं।

। और इन दवाओं में से किसी भी पदार्थ वाले अन्य पदार्थ, डिप्लॉक्सिलेट की तैयारी को छोड़कर, प्रति खुराक इकाई के अनुसार, 25 मिलीग्राम से अधिक नहीं। *Diphenoxylate* की गणना आधार के रूप में की जाती है, और डिसफेनॉक्सिलेट की खुराक के कम से कम एक प्रतिशत के बराबर एट्रोफिन सल्फेट की एक मात्रा।

। यूनिट और अविभाजित तैयारी में 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं की एकाग्रता के साथ और जो चिकित्सीय अभ्यास में स्थापित किया गया है।

। यूनिट और अविभाजित तैयारी में 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं की एकाग्रता के साथ और जो चिकित्सीय अभ्यास में स्थापित किया गया है।

डिफेनॉक्सिन युक्त, पेरडोजेज यूनिट की तैयारी, अधिकतम 0.5 मिलीग्राम डिफेनॉक्सिन की गणना आधार के रूप में की जाती है और एट्रोपिन सल्फेट की एक मात्रा कम से कम 5 प्रतिशत की मात्रा के बराबर होती है, जो आधार के रूप में गणना की जाती है, जो मिश्रण में मौजूद होती है।

इनमें से किसी भी दवा वाले पदार्थ, मौखिक उपयोग की तैयारी को छोड़कर 135 मिलीग्राम से अधिक डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफीन बेस प्रति खुराक इकाई या अविभाजित इकाई में 2.5 प्रतिशत से अधिक की एकाग्रता के साथ या 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं की एकाग्रता के साथ, 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं। अविभाजित तैयारी, बशर्ते कि इस तरह की तैयारी में साइकोट्रोपिक पदार्थों, 1971 पर कन्वेंशन के तहत नियंत्रित कोई भी पदार्थ शामिल नहीं है।

(२५) इसके बाद, केंद्र सरकार ने २९.१.९९ ३ दिनांकित अधिसूचना ने १ और अधिक दवाओं को "निर्मित दवाओं" के रूप में सूचित किया है। सभी 105 दवाओं में केंद्र सरकार द्वारा "निर्मित दवाओं" के रूप में अधिसूचित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा "निर्मित दवाओं" के रूप में अधिसूचित अधिकांश दवाओं को 1945 के नियमों के अनुसूचित एच'के तहत कवर किया गया है। दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम की धारा 3 (बी) इस प्रकार है: 'ड्रग'को परिभाषित करता है:-

"(बी)" ड्रग "में शामिल हैं-

(i) मानव या जानवरों के आंतरिक या बाहरी उपयोग के लिए सभी दवाएं और सभी पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिनका उपयोग मानव शरीर पर लागू तैयारी सहित मानव या जानवरों में किसी भी बीमारी या विकार की निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए किया जाता है। मच्छरों की तरह कीटों को हटाने के उद्देश्य से;

(ii) (iii) ऐसे पदार्थ (भोजन के अलावा) का उद्देश्य मानव शरीर के किसी भी कार्य की संरचना को प्रभावित करना है या इसका उपयोग [वर्मिन] या कीटों के विनाश के लिए किया जाना है जो मानव या जानवरों में बीमारी का कारण बनता है, जैसा कि से निर्दिष्ट किया जा सकता है आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर;

(iii) (iii) खाली जिलेटिन कैप्सूल सहित एक दवा के घटकों के रूप में उपयोग के लिए सभी पदार्थों का उद्देश्य; और

(iv) (iv) मानव या जानवरों में निदान, उपचार, शमन या रोग या विकार की रोकथाम में आंतरिक या बाहरी उपयोग के लिए इरादा ऐसे उपकरण, जैसा कि आधिकारिक गजट में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है, बोर्ड के साथ परामर्श;

(v) (26) १९४५ के नियमों के संदर्भ में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लाइसेंस देने के लिए शक्तियां प्रदान की हैं। 1945 के नियमों का भाग 1/होम्योपैथिक दवाओं के अलावा अन्य दवाओं की बिक्री के लिए प्रदान करता है। 1945 के नियमों के नियम 59 (1) ने परिकल्पना की है कि राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों के लिए इस भाग के उद्देश्य के लिए लाइसेंसिंग अधिकारियों की नियुक्ति करेगी जैसे कि निर्दिष्ट किया जा सकता है। नियम 59 के उप-नियम (2) ने 1945 के नियमों के अनुसूची एक्स 'में शामिल लोगों के अलावा, बिक्री या वितरण के लिए बेचने, स्टॉक, प्रदर्शन या प्रस्ताव के लिए लाइसेंस के अनुदान या नवीनीकरण के लिए प्रदान किया है, जो विशेष दवाओं से संबंधित है। आयात लाइसेंस के लिए, फॉर्म 19 या फॉर्म 19 ए में बनाया जाएगा, जैसा कि मामला हो सकता है, या अनुसूची एक्स 'में शामिल दवाओं के मामले में फॉर्म 19 सी में लाइसेंसिंग प्राधिकरण को बनाया जाएगा। 1945 के नियमों के नियम 60 ने परिकल्पना की है कि एक लाइसेंसिंग प्राधिकरण राज्य सरकार की मंजूरी के साथ एक आदेश द्वारा लाइसेंस पर हस्ताक्षर करने की शक्ति को लिखने के लिए कर सकता है और ऐसी अन्य शक्तियों को अपने नियंत्रण में किसी अन्य व्यक्ति को आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है। 1945 के नियमों का नियम 61 ड्रग्स बेचने के लिए लाइसेंस के रूपों के लिए प्रदान करता है।

नियम 62एक से अधिक स्थानों पर बिक्री से संबंधित है। नियम 62A फॉर्म 20 ए और 21ए में प्रतिबंधित लाइसेंस से संबंधित है। नियम 62बी फॉर्म 20ए या फॉर्म 21ए में लाइसेंस से पहले संतुष्ट होने के लिए शर्तों से संबंधित है। नियम 62सी थोक द्वारा ड्रग्स बेचने या मोटर वाहन से उसी को वितरित करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन से संबंधित है। नियम 62d के रूप में संबंधित है।

थोक द्वारा ड्रग्स बेचने या मोटर वाहन से ड्रग्स वितरित करने के लिए लाइसेंस। नियम 63 लाइसेंस की अवधि से संबंधित है। नियम 63A एक बिक्री लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रमाण पत्र से संबंधित है और नियम 63 बी लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रमाण पत्र से संबंधित है। नियम 64 फॉर्म 20, 20 बी, 20 एफ, 20 जी, 21 और 21 बी में लाइसेंस से पहले संतुष्ट होने के लिए शर्तों से संबंधित है या नवीनीकृत किया गया है। नियम 65 लाइसेंस की स्थिति से संबंधित है। नियम 65A लाइसेंस के लिए एक आवेदक द्वारा सुसज्जित अतिरिक्त जानकारी से संबंधित है या लाइसेंसिंग प्राधिकरण को लाइसेंसधारी। नियम 66 लाइसेंस को रद्द करने और निलंबन से संबंधित है। नियम 66A लाइसेंस रद्द करने की स्थिति में दवाओं के निपटान के लिए प्रक्रिया से संबंधित है। उक्त नियम 1945 के नियमों के भाग VI के अंतर्गत आते हैं, जिनके संबंध में शक्तियां राज्य सरकार को दी गई हैं।

(27) डी एंड सी अधिनियम की धारा 26 ए के संदर्भ में, केंद्रीय सरकार के पास दवा और कॉस्मेटिक के निर्माण आदि को प्रतिबंधित करने की शक्ति है सार्वजनिक हित में। यह प्रदान किया गया है कि किसी भी पूर्वाग्रह के बिना इस अध्याय में निहित अन्य प्रावधान यानी अध्याय IV, यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट है, कि किसी भी दवा या कॉस्मेटिक का उपयोग होने की संभावना है। मनुष्यों या जानवरों के लिए कोई जोखिम शामिल है या कोई भी दवा नहीं है। चिकित्सीय मूल्य का दावा किया गया है या इसके लिए दावा किया जाना है या सामग्री और ऐसी मात्रा में शामिल हैं जिनके लिए कोई चिकित्सीय नहीं है। औचित्य और यह कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक या समीचीन है। तब, उस सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, वह करने के लिए, ऐसी दवा या कॉस्मेटिक के निर्माण, बिक्री या वितरण को प्रतिबंधित करें।

डी एंड सी अधिनियम की धारा 26 बी के संदर्भ में, केंद्र सरकार के पास है। सार्वजनिक रूप से दवाओं के विनियमित या प्रतिबंधित, निर्माण आदि की शक्ति दिलचस्पी। यह प्रदान किया जाता है कि किसी अन्य प्रावधान के पूर्वाग्रह के बिना इस अध्याय में निहित यानी अध्याय IV, यदि केंद्र सरकार है। संतुष्ट है कि आपातकालीन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दवा आवश्यक है। महामारी या प्राकृतिक आपदाओं के कारण और जनता में ब्याज, यह आवश्यक या समीचीन है, तो, फिर, कि सरकार हो सकती है, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्माण को विनियमित या प्रतिबंधित करें, ऐसी दवा की बिक्री या वितरण।

(28) जो लाइसेंस निर्माताओं को जारी किए जाते हैं और अन्य विभिन्न व्यक्तियों को बेचने, स्टॉक, प्रदर्शन करने, बिक्री के लिए पेशकश करने या अनुसूचित 'सी', 'सी (1)' और 'एक्स में उल्लिखित दवाओं के अलावा अन्य दवाओं को वितरित करने के लिए पेशकश करते हैं।', कौन

1945 के नियमों के फॉर्म 20, 20ए और 20बी में जारी किए गए हैं। नियम 97 1945 के नियमों के भाग IX के अंतर्गत आता है जो होम्योपैथिक दवाओं के अलावा अन्य दवाओं की लेबलिंग और पैकिंग से संबंधित है। उक्त नियम 97 के संदर्भ में, आंतरिक उपयोग के लिए एक दवा के कंटेनर में विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा। 1945 के नियमों के नियम 97 (1) के तहत पढ़ा गया है:-

"97. दवाओं की लेबलिंग I- (1) आंतरिक उपयोग के लिए एक दवा का कंटेनर

(ए) यदि इसमें अनुसूची जी में निर्दिष्ट पदार्थ शामिल है, तो सावधानी के शब्दों के साथ लेबल किया जाता है: चिकित्सा पर्यवेक्षण के अलावा इस तैयारी को लेना खतरनाक है' - विशिष्ट रूप से मुद्रित और एक पंक्ति से घिरा हुआ है जिसके भीतर कोई दूसरा शब्द नहीं होगा;

(ब) यदि इसमें शेड्यूल H में निर्दिष्ट एक पदार्थ शामिल है, तो उसे प्रतीक RX के साथ लेबल किया जाता है और लेबल के बाएं शीर्ष कोने पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है और इसे निम्नलिखित शब्दों के साथ भी लेबल किया जाता है:-

अनुसूची एच ड्रग-वार्निंग: केवल एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पर्चे पर खुदरा द्वारा बेचा जाना ;

(ग) यदि इसमें शेड्यूल एच में निर्दिष्ट पदार्थ शामिल है और यह मादक दवाओं और साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 के 61) के दायरे में आता है, तो उन्हें प्रतीकों NRX के साथ लेबल किया जाएगा जो लाल और स्पष्ट रूप से बाएं शीर्ष पर प्रदर्शित होगा। लेबल के कोने, और निम्नलिखित शब्दों के साथ भी लेबल किया गया है:-

शेड्यूल एच ड्रग-वार्निंग: केवल एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पर्चे पर खुदरा द्वारा बेचा जाना ;

(d) यदि इसमें अनुसूची X में निर्दिष्ट पदार्थ शामिल है, तो प्रतीक XX के साथ लेबल किया जाता है जो कि लेबल के बाएं शीर्ष कोने पर दिखाए जाने वाले लाल रंग में होगा, और निम्नलिखित शब्दों के साथ भी लेबल किया जाएगा:-

'शेड्यूल X Drug-Warning: केवल एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पर्चे पर खुदरा द्वारा बेचा जाना;''

(२९) १९४५ के नियम, इसलिए विभिन्न दवाओं के लिए प्रदान करते हैं जो शेड्यूल 'सी', 'सी (1) ',' एच "और" एक्स 'में शामिल हैं। अनुसूची 'सी' जैविक और विशेष उत्पादों से संबंधित है। (1) 'अन्य विशेष उत्पादों से संबंधित है जिसमें विटामिन और तैयारी शामिल है जिसमें विटामिन शामिल हैं, जो कि एक रूप में नहीं किए जाने वाले रूप में नहीं हैं। लीवर अर्क और लीवर अर्क युक्त तैयारी एक रूप में नहीं किया जाता है। एंटीबायोटिक्स और तैयारी एक फॉर्म में नहीं किए जाने वाले रूप में नहीं की जाती है। दवाओं की लेबलिंग।'

(३०) जैसा कि पहले से ही कुछ साइकोट्रोपिक पदार्थों पर ध्यान दिया गया है और शेड्यूल 'एच' ड्रग्स ओवरलैपिंग कर रहे हैं। एनडीपीएस अधिनियम की अनुसूची में सीरियल नंबरों पर निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक पदार्थों का उल्लेख 1945 के नियमों के अनुसूची 'एच' में भी किया गया है:--

साइकोट्रोपिक पदार्थ का सीनियर नं।

30 अल्प्राजोलम

36 क्लोर्डियाजेपॉक्साइड

43 डायजेपाम

50 फ्लुराज़ेपम

56 लोराज़ेपम

64 नाइट्राज़ेपम

66

ऑक्साजेपाम

69 फेनोबार्बिटल

अनुसूची एच में दवा की नं।

15

अल्प्रज़ोलम

105

क्लोरडाएज़पोक्साइड

147

डायजेपाम

207

फ़्लुराज़ेपम

294

Lorazepam

360 नाइट्राज़ेपम

371 ऑक्साज़ेपम

396 फेनोबार्बिटल

(३१) १९४५ के नियमों के अनुसूची 'एच' में, जिन दवाओं के संबंध में दवाएं हैं, वे औषधीय या चिकित्सीय उपयोग के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए थोक बिक्री द्वारा दुरुपयोग किए गए हैं, ज्यादातर, सीरियल नंबर १३२ में कोडीन है,

सीरियल नंबर 146 में डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफेन और सीरियल नंबर 156 में इसके नमक को डीपेनोक्सिलेट शामिल किया गया है।

14.11.1985 की अधिसूचना के सीरियल नंबर 87 पर, दवा (+)-4-डाइमिथाइलमिनो-1, 2-डिपेनील-3-मिथाइल -2-ब्यूटोन प्रोपियोनेट (अंतर्राष्ट्रीय गैर-मालिकाना नाम जिसमें डेक्सट्रोप्रोपॉक्सिन है), और इसके लवण, तैयारी, प्रवेश, अर्क और इनमें से किसी भी दवा वाले अन्य पदार्थ, मौखिक उपयोग की तैयारी को छोड़कर, जिसमें 135 मिलीग्राम से अधिक डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफीन बेस प्रति खुराक इकाई या अविभाजित तैयारी में 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं, जिसमें अविभाजित तैयारियों में 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं है, जिसमें मौखिक उपयोग की तैयारी नहीं है, जिसमें अविभाजित तैयारी, 2.5 प्रतिशत से अधिक नहीं है। बशर्ते कि इस तरह की तैयारी में साइकोट्रोपिक पदार्थों के सम्मेलन के तहत नियंत्रित कोई भी पदार्थ शामिल नहीं है, 1971। इसलिए, 14.11.1985 की अधिसूचना के संदर्भ में, डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफीन एक दवा है, जिसे एक निश्चित अपवाद के साथ एक निर्मित दवा के रूप में अधिसूचित किया गया है, हालांकि संदर्भ में एक निश्चित अपवाद के साथ अधिसूचित किया गया है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2 (xi) (बी) और 1945 के नियमों के अनुसूची 'एच' में भी एक दवा है।

रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, पार्वान स्पास कैप्सूल में नमक डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफीन एचसीएल 74.90 मिलीग्राम और कैप्सूल सुभाष में डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफीन एचसीएल 74.96 मिलीग्राम का नमक शामिल था। मोहम्मद में। शमशाद बनाम पंजाब राज्य (2012 का CRM नंबर M-20282), पार्वान स्पा के 500 कैप्सूल बरामद किए गए थे, जो रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफीन एचसीएल में शामिल थे। ज्यादातर निर्मित दवाओं के संबंध में, जिनमें एक उल्लंघन होता है, जिसमें डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफीन, कोडीन होता है और ये याचिकाकर्ताओं के लिए सीखा वकील के अनुसार 'निर्मित दवाएं' नहीं हैं ताकि एनडीपीएस अधिनियम के दायरे में आ सकें। हालांकि, अधिसूचना दिनांक 14.11.1985 के संदर्भ में इन्हें विशेष रूप से 'निर्मित दवाओं' के रूप में उल्लेख किया गया है और इनका उल्लंघन एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत एक अपराध होगा, जो निर्मित दवाओं और तैयारी के

संबंध में उल्लंघन के लिए सजा से संबंधित है; हालांकि ये डी एंड .सी अधिनियम और 1945 के नियमों के तहत भी अपराध हो सकते हैं। यह सवाल कि अपवाद के लिए ये प्रदान करते हैं, यह अधिक परिणाम नहीं होगा क्योंकि ये एक में किए जाते हैं ।

थोक रूप और इस तरह से कि वे औषधीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन इसका उपयोग नशा के लिए किया जाता है और एक उत्तेजक प्रभाव प्राप्त होता है। ये ज्यादातर एक ट्रान्स में जाने के लिए शामक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा, जब इन्हें उचित प्राधिकरण या लाइसेंस के बिना एक थोक रूप में ले जाया जाता है, तो ये एनडीपीएस अधिनियम और एनडीपीएस नियमों के तहत प्रदान किए गए उल्लंघनों के भीतर आते हैं। प्रति खुराक उपयोग के लिए प्रदान किए गए अपवाद के भीतर इन के प्रश्न विशेष रूप से अनुचित होंगे, खासकर जब कोई उचित प्राधिकरण या लाइसेंस नहीं है। यह देखा जा सकता है कि धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम जो निर्मित दवाओं और तैयारी के संबंध में उल्लंघन के लिए सजा से संबंधित है, एनडीपीएस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या किसी भी नियम या आदेश या लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में अलग-अलग दंड प्रदान करता है। मैन्युफैक्चरर्स, पॉज़ेस, सेल, खरीद, ट्रांसपोर्ट्स, इंपोर्ट्स इंटर-स्टेट, एक्सपोर्ट्स इंटर-स्टेट या किसी भी निर्मित दवा या किसी भी प्रेजेंटेशन का उपयोग करता है, जिसमें किसी भी निर्मित दवा की मात्रा होती है, जिसके आधार पर कोई उल्लंघन हुआ है, अर्थात्, छोटी मात्रा, शामिल है। वाणिज्यिक मात्रा की तुलना में मात्रा कम लेकिन कम मात्रा से अधिक और वाणिज्यिक मात्रा को शामिल करना। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत पढ़ी जाती है:-

"21. निर्मित दवाओं और तैयारी के संबंध में उल्लंघन के लिए सजा। जो भी, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या किसी भी नियम या आदेश के उल्लंघन में, लाइसेंस की स्थिति या शर्त की स्थिति, विनिर्माण, निर्माण, बिक्री, खरीद, परिवहन, आयात करता है -स्टेट, अंतर-राज्य निर्यात करता है या किसी भी निर्मित दवा का उपयोग करता है या किसी भी निर्मित दवा वाली किसी भी तैयारी को दंडनीय होगा,--

(ए) जहां उल्लंघन में छोटी मात्रा शामिल होती है, एक शब्द के लिए कठोर कारावास के साथ, जो छह महीने तक हो सकता है, या ठीक है जो दस हजार रुपये तक, या दोनों के साथ हो सकता है;

(बी) जहां उल्लंघन में मात्रा शामिल होती है, वाणिज्यिक मात्रा से कम, लेकिन छोटी मात्रा से अधिक, एक शब्द के लिए कठोर कारावास के साथ, जो दस साल तक बढ़ सकता है और जुर्माना के साथ जो एक लाख रुपये तक विस्तारित हो सकता है /

71) जहां उल्लंघन में वाणिज्यिक मात्रा शामिल होती है, एक शब्द के लिए कठोर कारावास के साथ, जो दस साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो बीस साल तक बढ़ सकता है और यह भी जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो हो सकता है दो लाख रुपये तक विस्तार करें।

बशर्ते कि अदालत निर्णय में दर्ज किए जाने के कारणों के लिए, दो लाख रुपये से अधिक जुर्माना लगा सकती है। "

NDPS अधिनियम परिभाषित के खंड (VIIA) और (XXIIIA); 'वाणिज्यिक मात्रा' और 'छोटी मात्रा' निम्नानुसार है:-

"(VIIA)" वाणिज्यिक मात्रा ", मादक दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों के संबंध में, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से अधिक मात्रा में किसी भी मात्रा का मतलब है;

(xxiiiia) 'छोटी मात्रा', मादक दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों के संबंध में, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में किसी भी मात्रा का मतलब है। "

, अन्य गैर-मालिकाना नाम, रासायनिक नाम, छोटी मात्रा (ग्राम में) और वाणिज्यिक मात्रा (ग्राम/किलोग्राम में) क्रमशः। इसके बाद केंद्र सरकार ने 18.11.2009 दिनांकित अधिसूचना जारी की है ताकि नोट 3 के बाद नोट 4 को जोड़ने के लिए तालिका में 'छोटी मात्रा' और 'वाणिज्यिक मात्रा' को निर्दिष्ट करने वाली नशीली दवाओं और मनोवैज्ञानिक पदार्थों की '19.10.2001 की अधिसूचना के संदर्भ में साइकोट्रोपिक पदार्थों को निर्दिष्ट किया जा सके। उक्त अधिसूचना दिनांक 18.11.2009 के रूप में पढ़ती है:-

सूचनाएं, नई दिल्ली, 18 नवंबर, 2009 एस.ओ. 2941 (ई)।

पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) केंद्र सरकार, इसके द्वारा अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है।

1055 (ई), दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 अर्थात्:-

नोट 3 के बाद अंत में तालिका में, निम्नलिखित नोट डाला जाएगा, अर्थात्:-

"(4) स्तंभ 2 में दिखाए गए संबंधित दवाओं से संबंधित तालिका के कॉलम 5 और कॉलम 6 में दिखाए गए मात्रा पूरे मिश्रण या किसी भी समाधान या किसी एक या अधिक मादक दवाओं या उस विशेष दवा के किसी भी एक या अधिक मादक दवाओं के लिए लागू होगी। इन दवाओं के फॉर्म या आइसोमर्स, एस्टर, इथर और लवण, जिसमें एस्टर, इथर और आइसोमर्स के लवण शामिल हैं, जहां इस तरह के पदार्थ का अस्तित्व संभव है और न कि केवल इसकी शुद्ध दवा सामग्री।

(36) केंद्र सरकार ने, इसलिए, अधिसूचना दिनांक १९।१०.२००१ ने एक तालिका द्वारा विभिन्न मादक दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों की *and* कम मात्रा 'और *op* वाणिज्यिक मात्रा' को निर्दिष्ट किया है। 18.11.2009 दिनांकित अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कॉलम 5 में दिखाए गए मात्रा जो 'छोटी मात्रा' और कॉलम 6 से संबंधित है, जो कॉलम 2 में दिखाए गए संबंधित दवाओं से संबंधित तालिका की 'वाणिज्यिक मात्रा' से संबंधित है जो कि स्तंभ 2 में दिखाया गया है कि मादक दवा और साइकोट्रोपिक पदार्थ के नाम से संबंधित है, पूरे मिश्रण या किसी भी समाधान या किसी एक या अधिक मादक दवाओं या उस विशेष दवा के साइकोट्रोपिक पदार्थों के किसी भी या अधिक पदार्थों के लिए लागू करना है, जहां इस तरह के पदार्थ का अस्तित्व संभव है और नहीं बस इसकी शुद्ध दवा सामग्री। उक्त अधिसूचना का इरादा मादक दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों के उपयोग को रोकना और प्रतिबंधित करना है, जहां भी औषधीय या चिकित्सीय उपयोग के अलावा अन्य के लिए उक्त दवाओं का दुरुपयोग होता है। जैसा कि पहले से ही देखा जा चुका है कि

विभिन्न निर्मित दवाओं को सूचित किया गया है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 निर्मित दवाओं और तैयारी के संबंध में उल्लंघन के लिए सजा के लिए प्रदान करती है। निर्धारित सजा की मात्रा के संदर्भ में है। इसलिए, एक अपराधी को जो सजा दी जा सकती है, वह इस बात के लिए उत्तरदायी है कि वह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जिसमें शामिल दवा की मात्रा के उल्लंघन पर निर्भर है। उद्देश्य हेतु

मात्रा का निर्धारण करने के लिए कि क्या यह छोटी मात्रा है, वाणिज्यिक मात्रा से कम है, लेकिन छोटी मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है, अधिसूचना के संदर्भ में निर्धारित किया जाना है, जो कि एक तालिका प्रदान करता है, जैसा 18.11.2009 में यह उल्लेख करते हुए कि यह बताई गई है कि यह मात्रा में यह है कि कॉलम 2 में दिखाए गए दवाओं से संबंधित कम मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा है। खुराक के रूप में उस विशेष दवा आदि आदि, जहां भी इस तरह के पदार्थ का अस्तित्व संभव है, न कि केवल इसकी शुद्ध सामग्री।

(37) निर्मित दवाएं जिनमें से वर्तमान मामलों में एक उल्लंघन किया गया है, एक थोक रूप में बेचे, खरीदे गए वितरित, संग्रहीत, परिवहन, ले गए, ले गए हैं और ज्यादातर ये उचित लाइसेंस या प्राधिकरण के बिना हैं। ऐसी दवाओं के संबंध में जो थोक रूप में ले जाया जाता है, 18.11.2009 दिनांकित अधिसूचना लागू होगी और यह सवाल कि इन दवाओं में एक अपवाद शामिल नहीं होगा क्योंकि अपवाद लागू होंगे जब दवाएं औषधीय या चिकित्सीय उपयोग के लिए होती हैं। इसके अलावा, निर्मित दवाओं की मात्रा को प्रति कैप्सूल के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाना है जब इन्हें उचित लाइसेंस या प्राधिकरण के बिना किया जाता है। दूसरे शब्दों में, एक कैप्सूल में निर्मित दवा की मात्रा खुराक पर विचार नहीं किया जाना है, लेकिन एक साथ कैप्सूल की संख्या में खुराक को यह निर्धारित करने के उद्देश्य से माना जाता है कि क्या अधिसूचना में प्रदान किए गए अपवाद 14.11.1985 में दिए गए हैं। मादक पदार्थों और तैयारी की घोषणा के रूप में उल्लिखित दवाओं के रूप में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, निर्मित दवाओं से संबंधित धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम के उल्लंघन के मामले में, नोटिफिकेशन 18.11.2009 में से नोट 4 लागू होगा जो यह कहना है कि जिनके संबंध में एक उल्लंघन है, वह 'छोटी मात्रा' है, 'वाणिज्यिक मात्रा लेकिन छोटी मात्रा से अधिक या वाणिज्यिक मात्रा' पूरे मिश्रण या किसी भी समाधान या किसी एक या अधिक मादक दवाओं या उस विशेष दवा के मनोवैज्ञानिक पदार्थों के किसी भी या अधिक नशीली दवाओं के लिए लागू होती है, जहां इस तरह के पदार्थ का अस्तित्व संभव है और नहीं बस इसकी शुद्ध दवा सामग्री। इसलिए, सीरियल नं। 16, 35, 36, 37, 48, 58, 70, 76, 83 और 87 में अधिसूचना दिनांक के अपवादों का प्रश्न प्रदान किया जा रहा है।

14.11.1985 असंगत है जब इन दवाओं को एक थोक रूप में ले जाया जाता है और थोक की पूरी मात्रा को ध्यान में रखा जाता है और विशेष रूप से प्रति खुराक के अनुसार जब इन्हें डी एंड सी अधिनियम और 1945 के नियमों के उल्लंघन में किया जाता है। बिना वैध लाइसेंस के या बिना वैध प्राधिकरण के रखे, खरीदे, वितरित, संग्रहीत, परिवहन, ले जाया गया है।

(38) इसी तरह कुछ 'साइकोट्रोपिक पदार्थ' हैं जिनका उल्लेख एनडीपीएस अधिनियम की अनुसूची में किया गया है और जिनका उपयोग औषधीय उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। उक्त 'साइकोट्रोपिक पदार्थ' का निर्माण 1945 के नियमों के तहत दिए गए लाइसेंस की शर्तों के अनुसार किया जा सकता है। उन पदार्थों को छोड़कर, जिनका उल्लेख 1945 के नियमों के अनुसूची 'I' में नहीं किया गया है, जिसके उद्देश्य से एक लाइसेंस उक्त 1945 के नियमों के तहत दिया जा सकता है, अन्य जो लाइसेंस या प्राधिकरण के बिना हैं नियम जो उक्त बाद वाले प्रावधानों के तहत अपराध करेंगे। इसलिए, एक 'निर्मित दवा' का कब्जा, जिसे 14.11.1985 और 29.1.1993 या 'साइकोट्रोपिक पदार्थ' दिनांकित सूचनाओं के संदर्भ में सूचित किया गया है और जिसका उल्लेख एनडीपीएस अधिनियम के अनुसूची 1 में किया गया है। या डी एंड सी एक्ट। तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष ने एनडीपीएस अधिनियम का एक कठोर प्रावधान लागू किया है, जो डी एंड सी अधिनियम के सामान्य प्रावधान की तुलना में किसी भी परिणाम या महत्व का नहीं होगा।

(39) मैगनलाल छगगानलाल (पी) लिमिटेड में ग्रेटर बॉम्बे और अन्य (3) (3) (सात न्यायाधीशों बेंच) के नगर निगम में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अध्याय V-A के कुछ प्रावधानों की वैधता से संबंधित मामले पर विचार किया। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट और बॉम्बे गवर्नमेंट परिसर (बेदखली) अधिनियम 1955। अध्याय V-A को बॉम्बे म्यूनिसिपल एक्ट 1888 में 1961 के महाराष्ट्र अधिनियम 14 द्वारा पेश किया गया था। उक्त अध्याय V-A में धारा 105-A और 105-B में शामिल है। उन वर्गों के प्रावधानों के अनुसार, आयुक्त को निगम के परिसर के संबंध में निगम और बॉम्बे इलेक्ट्रिक आपूर्ति और परिवहन उपक्रम के महाप्रबंधक द्वारा या पट्टे पर ले जाने वाले परिसर के संबंध में आयुक्त, जो उसमें निहित है। के प्रयोजनों के लिए

(३) एयर १ ९ ४ एससी २०० ९

उपक्रम को बेदखली की कुछ शक्तियां प्रदान की गईं। किसी भी निगम परिसर का अनधिकृत व्यवसाय। के अनुसार धारा 105-बी, आयुक्त ने नोटिस द्वारा व्यक्ति को सेवा दी। अनधिकृत व्यवसाय, उसे खाली करने के लिए कह सकता है अगर उसने भुगतान नहीं किया है। दो महीने से अधिक की अवधि उसके कारण किराए या करों को वैध रूप से ऐसे परिसर के संबंध में, या उप-लेट, नियमों या शर्तों के विपरीत उनके व्यवसाय में, इस तरह के परिसर का पूरा या कोई हिस्सा; या प्रतिबद्ध, या कमिट कर रहा है, कचरे के ऐसे कृत्यों के रूप में भौतिक रूप से कम होने की संभावना है। मूल्य, या काफी हद तक उपयोगिता, परिसर की; या अन्यथा किसी भी शर्त, व्यक्त या निहित, के तहत किसी भी शर्त के उल्लंघन में काम किया। जिसे वह ऐसे परिसर पर कब्जा करने के लिए अधिकृत है; या यदि कोई व्यक्ति अंदर है। किसी भी निगम परिसर के अनधिकृत व्यवसाय; या कोई भी निगम। किसी भी व्यक्ति के कब्जे में परिसर निगम द्वारा आवश्यक है सार्वजनिक हित में। ऐसा आदेश देने से पहले, आयुक्त दिखाने के लिए संबंधित व्यक्ति को एक नोटिस जारी करने की आवश्यकता है। कारण क्यों बेदखली का एक आदेश नहीं बनाया जाना चाहिए और निर्दिष्ट करना चाहिए। आधार जिस पर बेदखली का क्रम बनाने का प्रस्ताव है। संबंधित व्यक्ति एक लिखित बयान दर्ज कर सकता है और दस्तावेजों का उत्पादन कर सकता है। और अधिवक्ता द्वारा आयुक्त के सामने पेश होने का हकदार था, अटॉर्नी या याचिकाकर्ता। इसलिए, आयुक्त को बेदखल करने की शक्ति थी। उन लोगों से संबंधित परिसर के संबंध में अनधिकृत व्यवसाय में निगम द्वारा पट्टे पर ले जाना, या लिया गया। के लिए आयुक्त

एक जांच करने के उद्देश्य में वही शक्तियां थीं, जिनमें निहित हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक नागरिक अदालत, जब एक सूट की कोशिश कर रहा है, किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को बुलाने और लागू करने का सम्मान और शपथ पर उसकी जांच करना; इसके अलावा, खोज और उत्पादन की आवश्यकता है। दस्तावेजों के रूप में भी किसी भी अन्य मामले के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है नियम। बॉम्बे गवर्नमेंट परिसर के प्रावधान (बेदखली अधिनियम) भी कम या ज्यादा समान थे, सिवाय इसके कि वे संबंधित थे। सरकारी परिसर और बेदखली के आदेश की शक्ति दी गई है। सक्षम प्राधिकारी एक डिप्टी कलेक्टर की तुलना में रैंक में कम नहीं है या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी इंजीनियर।

केवल अन्य मामला जिसके संबंध में सरकार के प्रावधान हैं परिसर (निष्कासन) अधिनियम बॉम्बे के प्रावधानों से भिन्न था । नगर निगम अधिनियम पूर्व अधिनियम की धारा 8-ए था । बशर्ते कि किसी भी सिविल कोर्ट के पास किसी भी सूट का मनोरंजन करने के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं होगा ।

या किसी भी व्यक्ति के बेदखली के संबंध में कार्यवाही के लिए धारा 4 में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर सरकारी परिसर उपयोग और व्यवसाय के लिए देय किराए या नुकसान के बकाया की वसूली ऐसे परिसर का। यह प्रस्तुत किया गया था कि दो प्रक्रियाएं थीं। निगम और राज्य सरकार के लिए उपलब्ध है, एक के माध्यम से एक सामान्य कानून के तहत और दूसरा दो कृत्यों के तहत, जो कि साधारण के तहत प्रक्रिया से अधिक कठोर और अधिक महत्वपूर्ण है। कानून, इसलिए, बाद में संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा मारा गया था। किसी भी दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति किस प्रक्रिया को अपनाई जा सकती है। बाद विस्तृत चर्चा, यह आयोजित किया गया था कि जहां एक प्रतिमा अधिक के लिए प्रदान करती है। साधारण प्रक्रिया से अलग कठोर प्रक्रिया पूरी तरह से कवर करती है। किसी भी दिशानिर्देश के बिना साधारण प्रक्रिया द्वारा कवर किए गए फ़ीलड उन मामलों की कक्षा जिसमें या तो प्रक्रिया का सहारा लिया जाना है, कानून अनुच्छेद 14. द्वारा मारा जाएगा। यहां तक कि, अपील के लिए एक प्रावधान का इलाज हो सकता है दोष। इसके अलावा, यदि प्रस्तावना और आसपास की परिस्थितियों से, के रूप में साथ ही कानून के प्रावधानों ने खुद को समझाया और प्रवर्धित किया। हलफनामे के अनुसार, आवश्यक दिशानिर्देशों का अनुमान लगाया जा सकता है, कानून नहीं होगा। अनुच्छेद 14. द्वारा मारा जा सकता है। इसके अलावा, जहां कानून ही केवल एक वर्ग को कवर करता है। मामलों में, कानून बुरा नहीं होगा। तथ्य यह है कि ऐसे मामलों में

कार्यकारी चुनेंगे कि किन मामलों को विशेष के तहत आजमाया जाना है। प्रक्रिया कानून की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी। इसलिए इस बात का विवाद कि दो प्रक्रियाओं की उपलब्धता एक में से एक होगी उन्हें, अर्थात्, विशेष प्रक्रिया, यह आयोजित किया गया था, का समर्थन नहीं किया गया था अधिकार का कारण। यह आगे आयोजित किया गया था कि कानून दोनों में ही था। मामलों की कक्षाओं ने स्पष्ट रूप से उनके पीछे के उद्देश्य को निर्धारित किया, अर्थात्, वह निगम और सरकार से संबंधित परिसर करना चाहिए। अनधिकृत रूप से बेदखल करने के मामले में शीघ्र प्रक्रिया के अधीन हो उन पर कब्जा करने वाले व्यक्ति। इसलिए, यह केवल इसलिए आयोजित किया गया था। प्रक्रिया एक

सिविल कोर्ट का मंच प्रदान करती है जबकि दूसरा प्रदान करता है। एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण का मंच, यह नहीं कहा जा सकता है कि बाद वाला है। आवश्यक रूप से अधिक कठोर और शानदार। लेख के निषेध को आकर्षित करने के लिए 14, यह आयोजित किया गया था कि पर्याप्त और गुणात्मक अंतर होना चाहिए। दो प्रक्रियाओं के बीच ताकि एक वास्तव में और काफी अधिक हो कठोर और पूर्वाग्रही। सुपरफाइन अंतर होने के लिए बाध्य होते हैं। दो प्रक्रियाएं निर्धारित की जाती हैं।

(४०) इसलिए, यह केवल इसलिए है क्योंकि अभियोजन पक्ष के लिए डी एंड सी अधिनियम और 1945 के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। इसके बाद किसी तरह का जुर्माना का परीक्षण करने के लिए एक बार नहीं होगा। ऐसे मामले जिनके संबंध में धारा 21 का उल्लंघन हुआ है। एनडीपीएस एक संदर्भ कार्य करता है जिसके लिए ऊपर बनाया गया है। एक विस्तृत एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों के परीक्षण के लिए प्रक्रिया प्रदान की गई है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36 ए विशेष द्वारा अपराध करने वाले अपराधों से संबंधित है। अदालत धारा 36 बी अपील और संशोधन से संबंधित है। धारा 36 सी से संबंधित है। एक से पहले कार्यवाही के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता का आवेदन विशेष न्यायालय और धारा 36 डी संक्रमणकालीन प्रावधान से संबंधित है। मामले में धारा 36 सी की, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान (जमानत और जमानत बांड के रूप में प्रावधानों सहित), आवेदन करने के लिए हैं। एक विशेष अदालत के समक्ष और उक्त के प्रयोजनों के लिए कार्यवाही प्रावधान, विशेष अदालत को सत्र की अदालत और माना जाता है। एक विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष रखने वाले व्यक्ति को माना जाता है एक लोक अभियोजक। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 4 से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के तहत अपराधों का परीक्षण। उप अनुभाग (२) इस बात की परिकल्पना है कि किसी भी अन्य कानून के तहत सभी अपराध हैं जो कानून है। भारतीय दंड संहिता के अलावा, जिसमें के तहत मामले शामिल होंगे एनडीपीएस अधिनियम, जांच की जाएगी, पूछताछ की, कोशिश की, और अन्यथा निपटाएगा समान प्रावधानों के अनुसार, अर्थात्, निहित प्रावधान धारा 4 के बाद लेकिन समय के लिए किसी भी अधिनियमन के अधीन जांच के तरीके या स्थान को विनियमित करना, पूछताछ करना, कोशिश करना या अन्यथा ऐसे अपराधों से निपटना। के तहत अपराधों के परीक्षण के लिए एनडीपीएस अधिनियम उचित प्रक्रिया और दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं। इसलिए, परीक्षण और अपराधों के अभियोजन के लिए प्रदान की गई प्रक्रिया एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी भी तरीके से अनुच्छेद 14 से नहीं मारा जाएगा संविधान; इसके अलावा, भले ही यह केवल उन मामलों का एक वर्ग कवर करता है जो हैं। एनडीपीएस में उल्लेख किया गया है कि यह बुरा नहीं होगा और इस तथ्य में कि ऐसे मामलों में

अभियोजन पक्ष चुनता है कि किन मामलों को विशेष के तहत आजमाया जाना है। प्रक्रिया एनडीपीएस अधिनियम और मात्र की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी दो प्रक्रिया की उपलब्धता उनमें से एक को विघटित नहीं करती है। NDPS अधिनियम के तहत विशेष प्रक्रिया। इसके अलावा, यह राज्य के लिए है। तय करें कि दो अधिनियमों में से किस में, एनडीपीएस अधिनियम या D & C अधिनियम अभियोजन लॉन्च किया जाने वाला अभियोजन है। यह उचित रूप से भी हो सकता है देखा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 80 के प्रावधानों की परिकल्पना है ।

D & C अधिनियम का आवेदन वर्जित नहीं है। धारा 80 एनडीपीएस अधिनियम के तहत पढ़ता है:-

"ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का आवेदन, 1940 पर रोक नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधान या इसके नियम अतिरिक्त में होंगे, न कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 (1940 के 23) या नियमों के अपमान में इसके बाद बना। "

(४१) विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य (४) के मामले में इस अदालत ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या एक थोक ड्रग डीलर, एक रिटेलर और उनके कर्मचारियों को अनुसूची और अनुसूची में निर्दिष्ट दवाओं में निपटने के लिए उचित और वैध लाइसेंस है। CI के साथ -साथ D & C अधिनियम के उन शेड्यूल में निर्दिष्ट ड्रग्स और 1945 के नियमों को NDPS अधिनियम के तहत दंडनीय दंड के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। धारा 80 एनडीपीएस अधिनियम का संदर्भ देने के बाद, यह आयोजित किया गया था कि एक व्यक्ति को एनडीपीएस अधिनियम के साथ -साथ डी एंड सी अधिनियम के तहत दोनों पर बहुत अच्छी तरह से मुकदमा चलाया जा सकता है, साथ ही उक्त अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए। यह आयोजित किया गया था कि केवल इसलिए कि एक व्यक्ति को डी एंड सी अधिनियम के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जाता है जो एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उस पर मुकदमा चलाने के लिए एक बार के रूप में काम नहीं करेगा। इसके बजाय अगर डी एंड सी अधिनियम के तहत किए गए अपराध भी एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के दायरे में आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले विरोधाभासों के कब्जे के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। दोनों कृत्यों, यह आयोजित किया गया था और एक अधिनियम के उल्लंघन का मतलब यह नहीं है कि दूसरे का कोई उल्लंघन नहीं है। इसलिए, केवल, क्योंकि अभियोजन लॉन्च किया जाता है और ट्रायल एनडीपीएस अधिनियम के तहत आयोजित किया जाता है, जिसे एक कठोर और एक प्रावधान माना जाता है, कार्यवाही की दीक्षा को अनुचित या बुरा नहीं कहा जा सकता

है। यदि यह किसी भी बाहरी कारणों या परिस्थितियों के लिए या माला के इरादे के साथ किया जाता है, तो निश्चित रूप से न्यायिक जांच और समीक्षा के अधीन होगा। परिस्थितियों में, जब एक निश्चित निर्मित दवा या एक साइकोट्रोपिक पदार्थ का उल्लंघन हुआ है और जो एनडीपीएस अधिनियम और एनडीपीएस नियमों के दायरे में आता है, तो कब्जे, बिक्री और परिवहन जो निषिद्ध है, या उचित के बिना किया जा रहा है लाइसेंस या कोई उचित प्राधिकरण के साथ, एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियोजन पक्ष निषिद्ध नहीं किया जाएगा और यह किसी भी तरीके से अवैध रूप से नहीं कहा जा सकता है।

(४) २०१३ (१) आरसीआर (सीआरएल।) ४२

(४२) याचिकाकर्ताओं के लिए सीखा वकील का विवाद है कि पुलिस अधिकारियों के वास्तविक प्रावधानों के बारे में अनजाने में हैं। एनडीपीएस अधिनियम और एनडीपीएस नियमों ने भी बोना फाइट को परेशान किया है। राज्य में रसायनज्ञों के अनुसार एक वैध और कानूनी लाइसेंस है। D & .C अधिनियम और 1945 के नियमों के प्रावधान। इस संबंध में उसे जरूरत है उल्लेख किया गया है कि अनावश्यक उत्पीड़न का उदाहरण वास्तव में है। दुर्भाग्यपूर्ण और इन्हें अदालतों द्वारा गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों में अभियोजन के लिए प्रदान करने सहित निर्मित दवाओं का सम्मान कठोर और कठोर है। ये हो गए हैं मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया। नीरन सिंह करम में सिंह पंजाबी बनाम जितेंद्र भीमराई बिजजा (5), माननीय सुप्रीम अदालत ने कड़े प्रावधानों के संबंध में एक मामला माना आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987. यह था देखा कि उक्त अधिनियम एक दंडात्मक क़ानून है। इसके प्रावधानों का मसौदा तैयार किया गया है कि वे न्यूनतम दंड प्रदान करते हैं और कुछ मामलों में बढ़ाया दंड भी। उक्त अधिनियम के प्रावधान से प्रस्थान थे साधारण कानून के बाद से साधारण कानून अपर्याप्त पाया गया और अपराधों के विशेष वर्ग से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं है। आतंकवादियों और विघटनकारी गतिविधियों से संबंधित। इसलिए, विशेष प्रावधान किए गए जो कुछ मामलों में कठोर हो सकते हैं, ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एक विशेष मंच बनाया गया, बशर्ते अपराधबोध का अनुमान लगाने के लिए, के संबंध में अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए। जमानत पर अपराधी की रिहाई, और में उपयुक्त बदलाव किए अपनी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए एक दृश्य के साथ प्रक्रिया। यह आयोजित किया गया था कि यह अच्छी तरह से है। उस क़ानून को बसाया गया जो एक कारावास की अवधि लागू करता है जो एक है। कानून के तहत आपराधिक अपराध को कड़ाई से माना जाना चाहिए। यह आगे था पूर्वोक्त आतंकवादियों के रूप में एक आपराधिक क़ानून का आह्वान करते समय आयोजित किया और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, अभियोजन कर्तव्य है। मामले के रिकॉर्ड और एकत्र किए गए दस्तावेजों से दिखाने के लिए बाध्य जांच के दौरान कि प्राइमा फेशियल से उभरने वाले तथ्य कानून के पत्र के भीतर एक अपराध का गठन करें। जब एक क़ानून प्रदान करता है।

निर्धारित सजा की तुलना में विशेष या बढ़ाया सजा देश के साधारण दंड कानूनों के तहत समान अपराधों के लिए, एक उच्चतर यह सुनिश्चित करने के लिए जज पर जिम्मेदारी और कर्तव्यों को डाला जाता है।
(५) एयर १ ९९ ० एससी १ ९ ६२

अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप का समर्थन करने के लिए प्राइमा फेशियल सबूत। इसलिए, जब कोई कानून गंभीर दंड के परिणाम वाले व्यक्ति से मिलने जाता है, तो अतिरिक्त देखभाल की जाती है कि जिन लोगों ने विधायिका को संचालन की व्यक्त भाषा द्वारा कवर करने का इरादा नहीं किया था, उन्हें कानून की भाषा को खींचकर नहीं किया जाता है। निरंजन सिंह करम सिंह पंजाबी बनाम जितेंद्र भीमराज बीजजा (सुप्रा) के मामले में उक्त अवलोकन को सीबीआई बॉम्बे (6) के माध्यम से संजय दत्त बनाम राज्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की बेंच द्वारा पुष्टि की गई थी। इसलिए, जब कोई कानून गंभीर दंडात्मक परिणाम वाले व्यक्ति से मिलने जाता है, तो अतिरिक्त देखभाल वास्तव में ली जाती है कि जिन लोगों ने विधायिका को संचालन की व्यक्त भाषा द्वारा कवर करने का इरादा नहीं किया था, उन्हें कानून की भाषा को खींचकर नहीं किया जाता है। हालांकि, उस खाते पर यह कहने के लिए कि जिन अपराधियों ने उल्लंघन किया है और नशीली दवाओं और निर्मित दवाओं की क्लैडस्टाइन बिक्री में लिप्त हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में सूचित किया गया है, इसके अलावा, साइकोट्रोपिक पदार्थों को केवल डी एंड सी अधिनियम के तहत दंडित किया जाना है। और 1945 के नियम कानून में सही स्थिति नहीं होंगे। यह राज्य के लिए अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए है जहां भी एनडीपीएस अधिनियम और एनडीपीएस नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, यह कहने के बजाय उक्त प्रावधानों के अनुसार उल्लंघन किया गया है कि ऐसे अपराधियों को केवल डी एंड सी अधिनियम और 1945 के नियमों के तहत दंडित किया जा सकता है। । दूसरे शब्दों में, जहां भी एनडीपीएस अधिनियम और एनडीपीएस नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन होता है, तो अपराध उक्त अधिनियम के दायरे और नियमों के भीतर आता है। इसलिए, अपराधियों के खिलाफ अभियोजन को एनडीपीएस अधिनियम के तहत वैध रूप से लॉन्च किया जा सकता है।

(४३) राजिंदर गुप्ता बनाम राज्य में दिल्ली उच्च न्यायालय।

नियम 65 (1), इंटर आलिया, प्रदान करता है कि अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी मनोवैज्ञानिक पदार्थ का निर्माण में डी और सी नियमों और डी और सी

अधिनियम के तहत दिए गए लाइसेंस की शर्तों के अनुसार होगा। दूसरे शब्दों में, जहां तक साइकोट्रोपिक पदार्थों का उल्लेख अनुसूची / में नहीं किया गया है

(६) JT१ ९९ ४ (५) एससी ५४०

0२००६ CRI.LJ६४

एनडीपीएस नियमों के लिए लेकिन एनडीपीएस अधिनियम की अनुसूची में उल्लेख किया गया है, उनका निर्माण डी और सी अधिनियम और नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और एनडीपीएस अधिनियम या एनडीपीएस नियमों द्वारा नहीं। नियम 66 साइकोट्रोपिक पदार्थों के कब्जे आदि से संबंधित है। उप-नियम (1) यह प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति के पास डी और सी नियमों द्वारा कवर किए गए किसी भी उद्देश्य के लिए "किसी भी साइकोट्रोपिक पदार्थ" के अधिकारी नहीं होंगे, जब तक कि वह एनडीपीएस नियमों के तहत किसी भी उक्त उद्देश्यों के लिए ऐसे पदार्थ के अधिकारी होने के लिए अधिकृत नहीं है। अभिव्यक्ति "किसी भी साइकोट्रोपिक पदार्थ" में स्पष्ट रूप से अनुसूची। में सूचीबद्ध लोगों के लिए एनडीपीएस नियमों के संदर्भ में संदर्भ है। नियम 64 एनडीपीएस नियमों के अध्याय VII में शासी नियम है। जब एक साइकोट्रोपिक पदार्थ को एनडीपीएस नियमों के लिए अनुसूची। में उल्लेख नहीं पाया जाता है, तो नियम 64 में निहित निषेध योग्यता योग्यता लागू नहीं होती है; ऐसा होने के नाते, इस तरह के एक मनोवैज्ञानिक पदार्थ के संबंध में, नियम 66 भी लागू नहीं होगा क्योंकि इसमें केवल उन साइकोट्रोपिक पदार्थ का संदर्भ है जो अनुसूची। में एनडीपीएस नियमों में शामिल हैं। एनडीपीएस नियमों का नियम 67 साइकोट्रोपिक पदार्थों के परिवहन से संबंधित है। यह स्पष्ट रूप से नियम 64 के प्रावधानों के अधीन है और स्पष्ट रूप से परिवहन, आयात अंतर-राज्य या उन साइकोट्रोपिक पदार्थों के अंतर-राज्य निर्यात का संदर्भ है जो अनुसूची। में एनडीपीएस नियमों में शामिल हैं। नियम में उन साइकोट्रोपिक पदार्थों के संबंध में कोई प्रयोज्यता नहीं होगी जो अनुसूची। में एनडीपीएस नियमों के लिए नहीं पाए जाते हैं। स्पष्ट रूप से, तब, बुप्रेनोर्फिन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में अनुसूची में NDPS नियमों में शामिल नहीं किया गया है, इसके निर्माण, कब्जे, बिक्री, परिवहन को NDPS नियमों द्वारा न तो निषिद्ध किया जाएगा और न ही विनियमित किया जाएगा और परिणामस्वरूप NDPS अधिनियम द्वारा। यह शेड्यूल एच ड्रग डी एंड सी अधिनियम और नियमों के कठोर के भीतर गिर जाएगा। "

(४४) उपरोक्त अवलोकन से पता चलता है कि एनडीपीएस नियमों के अनुसूची। में जिन साइकोट्रोपिक पदार्थों का उल्लेख किया गया है, वे एनडीपीएस अधिनियम के तहत अभियोजन पक्ष में हैं। इसमें यह जोड़ा जा सकता है कि उन दवाओं को जो केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से

14.11.1985 की अधिसूचना के संदर्भ में 'निर्मित दवा' के रूप में अधिसूचित किया जाता है और बाद में 29.1.1993 दिनांकित अधिसूचना एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत अभियोजन को लागू करेगी। इसलिए, प्रत्येक मामले में इसकी आवश्यकता होगी।

यह देखने के लिए कि क्या एक अपराधी द्वारा उल्लंघन करने के लिए कथित तौर पर जिस दवा के संबंध में दवा है, वह वास्तव में एनडीपीएस अधिनियम के उल्लंघन में है और यह अधिसूचित निर्मित दवाओं के संदर्भ में निर्धारित और जांच की जानी है जैसा कि दिनांक 14.11 में उल्लेख किया गया है। .1985 और 29.1.1993। एनडीपीएस अधिनियम के अनुसूची में उल्लिखित साइकोट्रोपिक पदार्थों का उल्लंघन और उसी के उल्लंघन में एनडीपीएस नियमों के लिए शेड्यूल 'I' भी एनडीपीएस अधिनियम के तहत अभियोजन पक्ष में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा, यह भी जांच करने की आवश्यकता होगी कि क्या दवा का प्रतिशत अनुमेय सीमा के भीतर है जैसा कि प्रदान किया गया है। हालांकि, थोक मात्रा, जिसके संबंध में एक उल्लंघन होता है या एक अनधिकृत व्यक्ति से बरामद किया जाता है, इस तथ्य का संकेत होगा कि इसका उपयोग औषधीय या चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था, लेकिन एक दवा के रूप में बहकावे या नशे के लिए या देने के लिए या देने के लिए एक अस्वास्थ्यकर रोमांच प्राप्त करने के लिए एक तेज उत्तेजक प्रभाव ताकि 'किंक' मिल सके। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि दवाओं को मादक दवाओं या साइकोट्रोपिक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिनका उपयोग औषधीय या चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि ड्रग के नशेड़ी या ड्रग ट्रैफिकर्स द्वारा दुरुपयोग किए जाते हैं, जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत अभियोजन पक्ष को वारंट करेंगे।

(४५) आम दवाएं जो ज्यादातर औषधीय और चिकित्सीय उपयोग के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग की जाती हैं, वे कोडीन, डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफीन और डिपेनोक्सिलेट जैसी दवाएं हैं। इनका उल्लेख सीरियल Nos.132, 146 और 156 में क्रमशः 1945 के नियमों की अनुसूची 'एच' में किया गया है, और क्रमशः सीरियल नोस .28, 33 और 44 में भी उल्लेख किया गया है। NDPS अधिनियम की धारा 2 के क्लॉस (VIA) और (xxiiiia) का संदर्भ। इसके अलावा, इनका उल्लेख सीरियल नं। 35, 87 और 58 में क्रमशः 14.11.1985 की अधिसूचना में किया गया है। अन्य दवाएं जो आमतौर पर दुरुपयोग की जाती हैं, वे 'अल्प्रजोलम, क्लोर्डियाज़ेप्रॉक्साइड, डेलोरेज़ेपम, डायजेपाम और ब्यूप्रेनोर्फिन' हैं, जो 'साइकोट्रोपिक पदार्थ' हैं और इसका उल्लेख सीरियल Nos.30, 36, 42, 43 और 92 शेड्यूल के संदर्भ में किया गया है। NDPS अधिनियम की धारा 2 का खंड (XXIII)। इन्हें आमतौर पर और व्यापक रूप से मादक पदार्थों के तस्करों द्वारा दुरुपयोग

किया जाता है, जो कि नशीली दवाओं की तस्करी में एक नशीला या उत्तेजक प्रभाव देने के लिए नशीली दवाओं की तस्करी में लिप्त है, न कि औषधीय या चिकित्सीय उपयोग के लिए। ड्रग एडिक्ट्स को एक समय में इन दवाओं का भारी डिस्चार्ज लेने के लिए जाना जाता है और यहां तक कि ड्रग निर्माता भी कुछ की थैली/बोतलों की पैकिंग के 100 टैबलेट पैक कर रहे हैं ।

इस तरह की दवाएं हालांकि उनमें से कुछ भी 1945 के नियमों की शेड्यूल 'एच' ड्रग के तहत आती हैं और उन्हें केवल एक पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा एक पर्चे पर खुदरा में बेचा जाना है या पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों, अस्पतालों, डिस्पेंसरी और नर्सिंग होम को आपूर्ति की जानी है लिखित रूप में हस्ताक्षरित आदेश के खिलाफ, जो कि 1945 के नियमों के नियम 65 (9) (ए) और (बी) के संदर्भ में दो साल की अवधि के लिए लाइसेंस द्वारा संरक्षित किया जाना है, जो के तहत पढ़ता है:-

"(9) (ए) अनुसूची एच या शेड्यूल एक्स में निर्दिष्ट पदार्थ खुदरा द्वारा एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के नुस्खे के अनुसार और अनुसूची एक्स में निर्दिष्ट पदार्थों के मामले में नहीं बेचे जाएंगे। डुप्लिकेट, जिसमें से एक प्रति लाइसेंसधारी द्वारा दो साल की अवधि के लिए बरकरार रखी जाएगी।

(बी) पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों, अस्पतालों, डिस्पेंसरी और नर्सिंग होम को अनुसूची एच या शेड्यूल एक्स में निर्दिष्ट दवाओं की आपूर्ति केवल लिखित रूप में हस्ताक्षरित आदेश के खिलाफ की जाएगी जो लाइसेंसधारी द्वारा दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

(४६) उपरोक्त नियम ६५ (९) (ए) और (बी) का एक अवलोकन यह बताता है कि अनुसूची 'एच' या शेड्यूल 'एक्स' में निर्दिष्ट पदार्थ एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पर्चे के अनुसार बेचे जाने हैं और अनुसूची 'X' में पदार्थों के मामले में पर्चे को डुप्लिकेट में होना है और उसी की एक प्रति को लाइसेंसधारी द्वारा दो साल के लिए बनाए रखा जाना है। पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों, अस्पतालों, डिस्पेंसरी और नर्सिंग होम के लिए उक्त अनुसूची 'एच' या शेड्यूल 'एक्स' में निर्दिष्ट दवाओं की आपूर्ति के रूप में इन्सोफ़र का संबंध है, वही केवल लिखित रूप में हस्ताक्षरित आदेश के खिलाफ किया जाना है जो कि होना चाहिए दो साल के लिए लाइसेंसधारी द्वारा संरक्षित। इसलिए, ऐसा नहीं है कि अनुसूची 'एक्स' में उल्लिखित दवाओं को किसी भी लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी तरीके से ले जाया जा सकता है जिसे वह पसंद करता है या उसे डी एंड सी अधिनियम और 1945 के नियमों के पालन के बिना प्राप्त किया जा सकता है। ड्रग्स जो ज्यादातर शेड्यूल 'एच' में दुरुपयोग

करते हैं, जैसा कि पहले से ही देखा गया है, हैं कोडेनी, डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफीन, डिपेनोक्सिलेट, सीरियल नोस .132, 146 और 156 शेड्यूल 'एच' पर इसका लवण। ये दवाएं 'निर्मित दवाओं' के दायरे में आती हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा सीरियल में 14.11.1985 की अधिसूचना के संदर्भ में अधिसूचित किया गया है।

Nos। 35, 87 और 58 क्रमशः और उसी का उल्लंघन धारा 21 NDPS अधिनियम के तहत दंडनीय है, जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधानों के उल्लंघन में, यानी NDPS अधिनियम या किसी भी नियम या आदेश या लाइसेंस की स्थिति के उल्लंघन में है, जो किसी भी नियम या आदेश की परिकल्पना करता है। विनिर्माण, अधिकारी, बिक्री, खरीद, परिवहन, आयात अंतर-राज्य, निर्यात अंतर-राज्य का निर्यात करता है या किसी भी निर्मित दवा का उपयोग करता है या किसी भी निर्मित दवा वाली किसी भी तैयारी को निर्मित दवा की मात्रा के अनुसार दंडनीय होगा, जिसमें एक उल्लंघन और एक उल्लंघन किया गया है। उसमें निर्दिष्ट है।

। नियम 2012 ") सूचना दिनांकित दिनांक 13.12.2012 धारा 78 द्वारा दी गई शक्तियों के अभ्यास में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 10 और 71 के साथ पढ़ी गई और इस ओर से आईआर को सक्षम करने वाली अन्य शक्तियां। नियम 8 अफीम के परिवहन के लिए प्रदान करता है। नियम 9 परिवहन के दौरान पैकेट खोलने के लिए निषेध के लिए प्रदान करता है। पंजाब एनडीपीएस नियम 2012 के अध्याय II से संबंधित अफीम और कोका लीफ को छोड़कर, इंटर-स्टेट, एक्सपोर्ट इंटर-स्टेट उपयोग, निर्मित दवाओं की खपत के कब्जे, परिवहन, खरीद, बिक्री, आयात अंतर-राज्य से संबंधित है। पंजाब एनडीपीएस नियम 2012 के नियम 17, 18 और 19 के रूप में पढ़ें:-

"17. निर्मित दवाओं के कब्जे। इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, किसी भी व्यक्ति को किसी भी निर्मित दवाओं के अधिकारी होने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि व्यक्ति इन नियमों के तहत समान रूप से अधिकृत नहीं है।

18. परिवहन, आयात अंतर-राज्य या निर्मित दवाओं के अंतर-राज्य का निर्यात। इन नियमों में अन्यथा प्रदान किए गए के रूप में सहेजें, नियम 17 में संदर्भित एक व्यक्ति परिवहन, आयात अंतर-राज्य और निर्यात अंतर-राज्य निर्मित दवाओं को तैयार कर सकता है, जो तैयार अफीम और कोका के अलावा अन्य ऐसी मात्रा में और इस तरह से, में निर्दिष्ट किया जा सकता है। ड्रग्स कंट्रोलर या डायरेक्टर आयुर्वेद, पंजाब, (आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध ड्रग्स के लिए) द्वारा जारी किया गया, जैसा कि मामला हो सकता है, या कोई अन्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया।

इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार इस ओर से सरकार द्वारा अधिकृत।

19. परिवहन का निषेध, अंतर-राज्य आयात या निर्यात अंतर-राज्य पोस्ट द्वारा। इन नियमों में अन्यथा प्रदान किए गए कुछ भी नहीं बचाएं, परिवहन, आयात अंतर-राज्य या निर्यात के माध्यम से निर्मित दवाओं के अंतर-राज्य निर्यात की अनुमति देने के लिए समझा जाएगा। "

(४) नियम १, के संदर्भ में, किसी भी व्यक्ति को किसी भी निर्मित दवाओं के अधिकारी नहीं हैं जब तक कि नियमों के तहत वैध रूप से अधिकृत नहीं किया जाता है। नियम 18 परिवहन, आयात अंतर-राज्य या निर्मित दवाओं के अंतर-राज्य निर्यात से संबंधित है। इसके संदर्भ में, एक व्यक्ति को नियम 17 में संदर्भित किया गया है यानी एक वैध रूप से अधिकृत व्यक्ति के पास निर्मित दवाओं के पास परिवहन, आयात अंतर-राज्य और निर्यात अंतर-राज्य निर्मित दवाओं को तैयार कर सकता है, जो तैयार अफीम और कोका लीफ के अलावा ऐसी मात्रा में और इस तरह से, के रूप में है, जैसे ड्रग्स कंट्रोलर या निदेशक आयुर्वेद पंजाब (यूनानी और सिद्ध ड्रग्स के लिए) द्वारा जारी किए गए परमिट में निर्दिष्ट किया जा सकता है, जैसा कि मामला हो सकता है, या इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार इस ओर से सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी हो सकता है। इसलिए, जिन मामलों में व्यक्ति निर्मित दवाओं को विशेष रूप से एक थोक रूप में परिवहन कर रहे हैं, जो औषधीय या चिकित्सीय उद्देश्यों के अलावा अन्य उपयोग के लिए है और उसके बाद, एक याचिका लेते हुए कि वे 1945 के नियमों के तहत वैध लाइसेंस धारक हैं, इसे होना चाहिए यह पता लगाया गया कि क्या उनके पास पंजाब एनडीपीएस नियम 2012 के नियम 18 के तहत जारी किया गया एक परिवहन परमिट है। नियम 19 के संदर्भ में, परिवहन, आयात अंतर-राज्य या निर्यात अंतर-पोस्ट के माध्यम से निर्मित दवाओं की स्थिति निषिद्ध है। नियम 23 परिवहन और निर्यात अंतर-राज्य के लिए पास के अनुदान से संबंधित है। के रूप में वही पढ़ता है:-

"23. परिवहन और निर्यात अंतर-राज्य के लिए पास का अनुदान। एक इंस्पेक्टर एक लाइसेंस प्राप्त निर्माता या लाइसेंस प्राप्त डीलर को अनुदान दे सकता है, फॉर्म नंबर ND-3 में एक पास और परिवहन और निर्यात अंतर के

लिए फॉर्म नंबर *ND-4*- निर्मित दवाओं की स्थिति, तैयार अफीम और कोका लीफ्स के अलावा उस मात्रा से अधिक नहीं है जिसके पास वह अधिकार है:

बशर्ते कि इस तरह के परिवहन और निर्यात पास को राज्य या गंतव्य जिले के सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित परमिट के उत्पादन को छोड़कर नहीं दिया जाएगा।

निर्मित दवाओं के अंतर-राज्य का निर्यात करें, तैयार अफीम और कोका लीफ्स के अलावा उस मात्रा से अधिक नहीं है, जिसके पास वह कब्जा करने का हकदार है। निर्यात पास राज्य या गंतव्य जिले के सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित परमिट के उत्पादन को छोड़कर नहीं दिया जाना है। पंजाब एनडीपीएस नियम 2012 के नियम 2 (xii) में 'पास' को नियमों के तहत दिए गए पास का अर्थ परिभाषित किया गया है; इसके अलावा, नियम 2 (XIII) के संदर्भ में 'परमिट' को नियमों के तहत दिए गए परमिट का अर्थ परिभाषित किया गया है। पंजाब एनडीपीएस नियम 2012 का नियम 24 चिकित्सा व्यवसायी और चिकित्सा संस्थानों द्वारा दवाओं के कब्जे से संबंधित है। के रूप में वही पढ़ता है:-

"24. चिकित्सा व्यवसायी और चिकित्सा संस्थानों द्वारा दवाओं का कब्जा। (1) एक चिकित्सा व्यवसायी, जो इस नियम के उप-नियम (4) के प्रावधान के तहत विधिवत पंजीकृत है, तैयार अफीम और कोका के अलावा अन्य निर्मित दवाओं की निम्नलिखित मात्रा में हो सकता है अपने अभ्यास में उपयोग के लिए लीफ्स और बिक्री के लिए नहीं -

(i) मॉर्फिन (सभी रूपों में) 5 ग्राम

(ii) Pethidine इंजेक्शन 5 ग्राम

(iii) fentanyl (सभी रूपों में) 1 ग्राम

(iv) फू-फेंटेनल (सभी रूपों में) 1 ग्राम

(v) 30 ग्राम आयुर्वेद और यूनीनी दवाओं के रूप में औषधीय अफीम जिसमें तैयारी में 0.2 प्रतिशत से अधिक मॉर्फिन होते हैं,

(vi) किसी भी अन्य निर्मित दवा 100 खुराक:

बशर्ते कि दवाओं के स्वदेशी प्रणालियों के एक चिकित्सा व्यवसायी, केवल उन निर्मित दवाओं के अधिकारी हो सकते हैं, जो चिकित्सा की स्वदेशी प्रणाली में शामिल हैं:

आगे बशर्ते कि दवा नियंत्रक या निदेशक, आयुर्वेद पंजाब, जैसा कि मामला हो सकता है, पूर्व अनुमोदन के साथ

सरकार, किसी भी चिकित्सा व्यवसायी को किसी भी बड़ी मात्रा में पूर्वोक्त निर्मित दवाओं के अधिकारी होने के लिए अधिकृत करती है। स्पष्टीकरण। उनके अभ्यास में शब्द का उपयोग इंजेक्शन, सर्जिकल संचालन या चिकित्सा व्यवसायी की उपस्थिति में या अन्य उभरते मामलों में दवाओं के वास्तविक प्रत्यक्ष प्रशासन को शामिल करता है।

(२) उप-नियम (४) के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक चिकित्सा संस्थान, तैयार अफीम और कोका लीफ के अलावा अन्य निर्मित दवाओं की ऐसी मात्रा में हो सकता है, जैसा कि समय-समय पर ड्रग्स कंट्रोलर या निदेशक द्वारा अनुमति दी जा सकती है, आयुर्वेद, पंजाब, जैसा कि मामला हो सकता है, ध्यान में रखते हुए चिकित्सा चिकित्सकों की संख्या और उपचार के तहत रोगियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए।

(३) (i) एक चिकित्सा व्यवसायी, जिसे उप-नियम (1) या एक चिकित्सा संस्थान के तहत निर्मित दवाओं के अधिकारी होने की अनुमति है, जिसे उप-नियम (2) के तहत इस तरह की दवाओं के अधिकारी होने की अनुमति है, एक से अपनी आपूर्ति प्राप्त करेगा लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ या लाइसेंस प्राप्त डीलर या लाइसेंस प्राप्त निर्माता केवल एक रजिस्टर दिखाते हुए रसीदों के साथ-साथ प्रत्येक दवा के निपटान को बनाए रखेंगे। रजिस्टर फॉर्म नंबर ND-5 में होगा;

(ii) एक अलग रजिस्टर या रजिस्टर का एक अलग हिस्सा दवाओं और तैयारी में से प्रत्येक को सौंपा जाएगा।

(iii) रजिस्टर में प्रविष्टियाँ उस दिन पर की जानी चाहिए जिस दिन निर्मित दवाओं को प्राप्त किया जाता है या उनके साथ भेजा जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि चिकित्सा व्यवसायी को खुद को रजिस्टर में प्रवेश करना चाहिए, उसके द्वारा या उसकी देखरेख के तहत प्रशासित

दवाओं के विवरण, लेकिन प्रविष्टियों को प्रवेश की तारीख या निम्नलिखित तारीख पर उसके द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। जहां एक चिकित्सा व्यवसायी एक से अधिक परिसरों में अभ्यास करता है, प्रत्येक परिसर में रखी गई दवाओं का एक अलग खाता बनाए रखा जाएगा।

(iv) प्रत्येक प्रविष्टि की आवश्यकता होती है और इस तरह की प्रविष्टि का प्रत्येक सुधार स्याही में किया जाना चाहिए और कोई रद्दीकरण, विस्मरण या कोई भी नहीं होना चाहिए

परिवर्तन रजिस्टर में किसी भी प्रविष्टि से किया जाएगा और किसी भी प्रविष्टि के किसी भी सुधार को सीमांत नोट या फुटनोट के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिसे उस तारीख को निर्दिष्ट करना होगा जिस पर सुधार किया गया है।

(iv) एक चिकित्सा व्यवसायी या एक चिकित्सा संस्थान के कब्जे में निर्मित दवाओं का स्टॉक और इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण के लिए संबंधित खाते खुले रहेंगे। दवा नियंत्रक या निदेशक, आयुर्वेद पंजाब द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता होगी, चिकित्सा व्यवसायी या एक चिकित्सा संस्थान, जैसा कि मामला हो सकता है, निर्मित दवाओं के लेनदेन से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करें, जैसा कि मांग की जा सकती है।

(vi) यदि किसी दूत को मेडिकल प्रैक्टिशनर या मेडिकल इंस्टीट्यूशन द्वारा निर्मित दवाओं की डिलीवरी लेने के लिए भेजा जाता है, तो दूत को एक प्राधिकरण दिया जाना चाहिए, लिखित रूप में, हस्ताक्षरित और दूत को उसके हस्ताक्षर के साथ नाम से निर्दिष्ट करना और उसके हस्ताक्षर और उसके हस्ताक्षर के साथ निर्दिष्ट करना चाहिए। ड्रग्स प्राप्त करने के लिए, दोनों ने सत्यापित किया। एक लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ, लाइसेंस प्राप्त डीलर या एक लाइसेंस प्राप्त निर्माता को मैसेंजर को ड्रग्स देने के लिए मना किया जाता है, अगर वह इतना अधिकृत नहीं है।

(vii) चिकित्सा व्यवसायी या एक चिकित्सा संस्थान ड्रग्स को ताला और कुंजी के नीचे रखेगा।

(viii) एक रोगी के घर में ड्रग्स ले जाने के दौरान, चिकित्सा व्यवसायी निर्मित दवाओं की सुरक्षित हिरासत के लिए पूर्ण सावधानी बरतेंगे।

निर्मित दवाओं के चोरी और नुकसान को निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाना चाहिए।

(ix) रजिस्टर और डे बुक सहित सभी रिकॉर्ड को अंतिम प्रविष्टि की तारीख से दो साल से कम नहीं रखा जाना चाहिए।

(४) एक चिकित्सा व्यवसायी या एक चिकित्सा संस्थान, जो अभ्यास में उपयोग के लिए निर्मित दवाओं के पास या वितरण के लिए इच्छुक है, ड्रग्स कंट्रोलर या निदेशक, आयुर्वेद पंजाब के लिए किए गए आवेदन पर पंजीकृत हो जाएगा, जैसा कि मामला हो सकता है, ऐसे शुल्क के साथ, इस तरह के शुल्क के साथ। जैसा कि समय - समय पर सरकार द्वारा सूचित किया जा सकता है। इस तरह के पंजीकरण का पूर्ण विवरण होगा।

फॉर्म नंबर ND-6 में एक रजिस्टर में बनाए रखा गया। ड्रग्स कंट्रोलर या डायरेक्टर आयुर्वेद, पंजाब, मेडिकल प्रैक्टिशनर या मेडिकल इंस्टीट्यूशन के पंजीकरण के तुरंत बाद, फॉर्म नंबर एनडी -7 में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करते हैं, जो निरीक्षण के लिए इंस्पेक्टर द्वारा मांग पर उत्पादित किया जाएगा।

(५०) उपरोक्त नियम चिकित्सा व्यवसायी और चिकित्सा संस्थानों द्वारा दवाओं के कब्जे के लिए विवरण, आवश्यकताएं देते हैं। नियम 26 व्यक्तिगत उपयोग के लिए कब्जे से संबंधित है। के रूप में वही पढ़ता है:-

"26. व्यक्तिगत उपयोग के लिए कब्जा। एक व्यक्ति, एक चिकित्सा व्यवसायी के पर्चे पर, ऐसी मात्रा में निर्मित दवाओं के अधिकारी हो सकते हैं, जो उसे औषधीय उद्देश्यों के लिए एक लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ द्वारा बेचा जा सकता है, जैसा कि एक समय में उपयोग के लिए आपूर्ति की गई है। इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार।"

पंजाब एनडीपीएस नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार उपयोग करें। उक्त पंजाब एनडीपीएस नियम, 2012 आगे एक रसायनज्ञ और नियम 27 के संदर्भ में एक डीलर को लाइसेंस देने के लिए प्रदान करें, नियम के संदर्भ में एक लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ द्वारा निर्मित दवाओं की बिक्री 28, नियम 29 के संदर्भ में एक लाइसेंस प्राप्त डीलर द्वारा निर्मित दवाओं की बिक्री, नियम 30 के संदर्भ में एक निर्माता को लाइसेंस का अनुदान। ये पंजाब एनडीपीएस नियम, 2012 व्यापक हैं और उस तरीके को विनियमित करते हैं जिसमें एक निर्मित दवा बेची जानी है, परिवहन और प्रशासित। खतरनाक पहलू ड्रग एडिक्ट्स और ड्रग टैफिकर्स द्वारा निर्मित दवाओं का दुरुपयोग है जो स्पष्ट रूप से औषधीय या चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए नहीं है। इसलिए, इस खतरे पर अंकुश लगाने के लिए एनडीपीएस अधिनियम और एनडीपीएस नियमों के उल्लंघन के लिए एनडीपीएस अधिनियम के कड़े प्रावधानों को लागू करना अनिवार्य है।

(५२) अभियुक्त के लिए दिखाई देने वाले अधिवक्ताओं का विवाद यह है कि यहां तक कि जहां व्यक्ति वैध रूप से ड्रग्स ले जा रहे हैं, उन्हें पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है। इसके अलावा, यहां तक कि जहां दवा एक निर्मित दवा; मादक दवा या साइकोट्रोपिक पदार्थ नहीं हो सकती है,

दवा के कब्जे में व्यक्ति को परेशान किया जाता है। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य सरकार के लिए आवश्यक कदम उठाना होगा। मादक नियंत्रण ब्यूरो ('एनसीबी' - शॉर्ट के लिए) द्वारा जारी किए गए निर्देश हालांकि एनसीबी द्वारा जांच के प्रयोजनों के लिए हैं, लेकिन उन्हें दिशानिर्देशों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। खेत सिंह बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट (8) इस प्रकार देखा गया:-

"नशीले पदार्थों के नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बाद एनडीपीएस अधिनियम के दायरे में आने वाले अपराधों की जांच के अधिकारी अधिकारी द्वारा पालन किया जाना है, भले ही इन निर्देशों में कानून का बल नहीं है। अधिकारियों का मार्गदर्शन करने और यह देखने के लिए कि जांच के अधिकारी द्वारा एक निष्पक्ष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। यह सच है कि जब जांच या खोज के दौरान एक कंट्रॉल लेख जब्त किया जाता है, तो एक जब्ती महाज़ार को मौके पर तैयार किया जाना चाहिए कानून के अनुसार। हालांकि, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, जिनमें अधिकारी के लिए मौन को मौके पर तैयार करने के लिए अधिकारी के लिए यह संभव नहीं था, क्योंकि यह एक मौका वसूली हो सकती है और अधिकारी के पास एक जब्ती महाज़ार को तैयार करने की सुविधा नहीं हो सकती है मौके पर ही। यदि जब्ती उस स्थान पर प्रभावित होती है जहां कोई गवाह नहीं हैं और कंट्रॉल लेख या अन्य अपेक्षित सुविधाओं को तौलने के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो अधिकारी बाद के चरण में जब्ती महाज़ार को तैयार कर सकते हैं और जब सुविधाएं उपलब्ध हैं, बशर्ते कि ऐसा करने के लिए उचित और उचित आधार हों। उस घटना में, जहां जब्ती महाज़ार को बाद के चरण में तैयार किया जाता है, तो अधिकारी को अपने कारणों को इंगित करना चाहिए कि उसने वसूली के स्थान पर महाज़ार को क्यों तैयार नहीं किया था। यदि जब्ती महाज़ार को तैयार करने में कोई देरी हो रही है, तो यह आरोपी से कथित रूप से जब्त किए गए कंट्रॉल लेख के साथ छेड़छाड़ करने का अवसर दे सकता है। यह भी आरोप लगाया जा सकता है कि जब्त किए गए लेख को अपने आप में प्रतिस्थापित किया गया था और कुछ अन्य वस्तुओं को आरोपी को गलत तरीके से फंसाने के लिए लगाया गया था। इन संदिग्ध परिस्थितियों से बचने के लिए और खोज के संबंध में एक उचित प्रक्रिया है

0 २००२ (२) आरसीआर (ctrl) २

और जब्ती, यह हमेशा उस स्थान पर जब्ती महाजार को तैयार करना वांछनीय होता है, जहां से कंटडी लेखों को हिरासत में ले लिया गया था। "

(५३) उपरोक्त टिप्पणियों से पता चलता है कि एनसीबी द्वारा जारी किए गए निर्देश दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं। यहां तक कि अन्यथा, प्रक्रियात्मक प्रावधानों का उल्लंघन जो आम तौर पर एक अपराधी के लिए एक उचित और पर्याप्त अवसर की पुष्टि करने के लिए होता है, उसकी रुचि में कल्पना की जाती है और प्रक्रियात्मक प्रावधान का उल्लंघन स्वचालित रूप से जांच में नहीं आता है जब तक कि यह न्याय की विफलता या नहीं दिखाया जाता है। परिणाम में पूर्वाग्रह हुआ। इसके अलावा, थाना सिंह बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (७) में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों के शीघ्र परीक्षण के लिए दिशा -निर्देश जारी किए हैं। उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रत्येक राज्य को विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया है जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत विशेष रूप से अपराधों के साथ सौदा करेगा। उक्त दिशा इंटर आलिया एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों से विशेष रूप से निपटने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना के लिए प्रदान करती है; एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई भी अदालत एक पार्टी के अनुरोध पर स्थगन देने के लिए नहीं है, सिवाय इसके कि परिस्थितियां पार्टी के नियंत्रण से परे हैं; जहां एक गवाह की परीक्षा उसी दिन संपन्न नहीं होती है, जिसकी जांच लगातार दिनों में की जाती है, लेकिन महीनों तक फैली हुई अलग -अलग तारीखों पर नहीं; तीन से चार दिनों की ब्लॉक अवधि में लगातार तारीखों पर एक गवाह की परीक्षा और क्रॉस परीक्षा का संचालन करना; आधिकारिक गवाहों के समय के साक्ष्य को बचाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 293 का अधिकांश उपयोग करके हलफनामों के रूप में लिया जाना चाहिए; प्रत्येक राज्य में मादक प्रयोगशालाओं तक पहुंच है ताकि एनडीपीएस के उद्देश्य के लिए एकत्र किए गए नमूने जांच के लिए उन्हें समय पर आधार पर कार्य करें; प्रयोगशालाओं द्वारा नमूनों के परीक्षणों को पूरा करने के बाद, इस मामले से संबंधित सभी पक्षों के लिए समान का परिणाम दिया जाना चाहिए और एनडीपीएस अधिनियम के तहत रिटेस्टिंग/री-सैपलिंग के लिए कोई भी अनुरोध नहीं किया जाएगा, हालांकि यह निश्चित रूप से एक मामला है, हालांकि ये हो सकते हैं, हालांकि, पीठासीन अधिकारी द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए बेहद असाधारण परिस्थितियों में अनुमति दी जाए जांच

और परीक्षण की प्रगति की निगरानी के लिए एनडीपी मामलों से निपटने वाले सभी विभागों द्वारा नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। प्रत्येक के लिए एक 'पेरीवी' अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी होना चाहिए

(९) २०१३ (१) आरसीआर (सीआरएल।) ४६१

अदालत जो उस अदालत के लिए सौंपे गए नोडल अधिकारी को दिनों की कार्यवाही की रिपोर्ट करेगा; जिला और सत्र न्यायाधीश लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए एक सिफारिश करेंगे, जो प्रशासनिक न्यायाधीश/पोर्टफोलियो न्यायाधीश के परामर्श से न्याय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चार्ज-शीट और अन्य दस्तावेजों की आपूर्ति को भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान किया जाना चाहिए, हालांकि, इस दिशा को उसी की हार्ड प्रतियों के विकल्प के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जो अदालत की कार्यवाही के लिए अपरिहार्य हैं। याचिकाकर्ताओं के लिए सीखा वकील का विवाद, जिसमें गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है, यह है कि एफएसएल की रिपोर्टों में देरी हो रही है, जो एक कथित अपराधी के अनावश्यक रूप से प्रवेश करती है, भले ही ड्रग्स जिसके साथ वह एक उल्लंघन करने के लिए आरोपित है, वह अनुमेय सीमा के भीतर हो सकता है। थाना सिंह के मामले (सुप्रा) में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। इसने केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (CFSL) की संख्या पर ध्यान दिया है जो संचालन में हैं और जो स्थापित किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में CFSL ऑपरेशन में है। इसने हरियाणा राज्य में राज्य और क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की संख्या पर भी ध्यान दिया है, पंजाब राज्य में एक मुख्य राज्य एफएसएल और दो क्षेत्रीय एफएसएल है, एक मुख्य राज्य एफएसएल है। यह देखा गया है कि इन प्रयोगशालाओं का एक गुणात्मक और मात्रात्मक समग्र रूप से वर्तमान मामलों की स्थिति को कम करने के लिए आवश्यक है, जिसके लिए निम्नलिखित दिशाएं जारी की गई हैं:-

(1) केंद्र को देश के विभिन्न हिस्सों से सीएफएसएल तक समान पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। वर्तमान चार सीएफएसएल केवल उत्तरी और देश के पश्चिमी और पूर्वी भागों के कुछ क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसलिए, पाइपलाइन में तीनों के अलावा, अधिक CFSL स्थापित किए जाने चाहिए, विशेष रूप से देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों की जरूरतों को पूरा करने के लिए।

(2) राज्यों के अनुरूप दिशाएं जारी की जाती हैं। कई राज्यों में नमूनों के विश्लेषण की सुविधा के लिए कोई मौजूदा बुनियादी ढांचा नहीं है और

इसलिए, उन्हें जांच के लिए देश के अन्य हिस्सों में प्रयोगशालाओं में भेजने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए, प्रत्येक राज्य को स्थापित करने के लिए आवश्यक है।

राज्य-स्तरीय और क्षेत्रीय-स्तरीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं। हालांकि, ऐसी प्रयोगशालाओं की संख्या के रूप में निर्णय राज्य में मामलों के बैकलॉग पर निर्भर करेगा।

(३) उपर्युक्त अधिकारियों को तकनीकी कर्मचारियों के पर्याप्त रोजगार और सुविधाओं और संसाधनों के प्रावधान को सुनिश्चित करना चाहिए, उनके तहत फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की सुविधाओं के उचित, सुचारू और कुशल चलने के प्रयोजनों के लिए और प्रयोगशालाओं को एजेंसियों को अपनी रिपोर्ट को तेजी से प्रस्तुत करना चाहिए संबंधित।

(४) फोरेंसिक साइंस सर्विसेज के निदेशालय, गृह मामलों के मंत्रालय को, विभिन्न फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में उपकरणों के मानकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए ताकि वे परिणाम को रोकने के लिए और एक मुकदमेबाज को उस आधार पर परीक्षण के परिणामों को चुनौती देने के अवसर को अस्वीकार कर सकें।

(५४) वास्तव में नमूने के परीक्षण में देरी एक कथित अपराधी के लिए पूर्वाग्रह में परिणाम करती है क्योंकि परिणाम उपलब्ध होने तक कॉन्ट्राबैंड के संबंध में कोई निश्चित निश्चितता नहीं हो सकती है, जिसके संबंध में एक उल्लंघन हुआ है या जो बरामद किया गया है। ऐसे मामलों में अंतिम एफएसएल रिपोर्ट के परिणाम का इंतजार करने के लिए जहां देरी होने की संभावना है, अभियुक्त को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। सुखवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (10) में, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस प्रकार आयोजित किया गया है:-

"... कमलेंद्र प्रताप सिंह बनाम इस अदालत के फैसले के बाद। आवेदन। हमारी राय में, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के

मद्देनजर उचित दृष्टिकोण है जो हर व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

(१०) (२०० ९) ७एससीसी ५३ ९

जब कोई व्यक्ति नियमित जमानत के लिए आवेदन करता है, तो अदालत संबंधित रूप से कुछ दिनों के बाद उस आवेदन को सूचीबद्ध करती है ताकि वह उस केस डायरी को देख सके जिसे पुलिस अधिकारियों से प्राप्त करना होगा और इस बीच आवेदक को जेल जाना होगा। यहां तक कि अगर आवेदक को उसके बाद जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो उसकी प्रतिष्ठा समाज में अपूरणीय रूप से धूमिल हो सकती है। एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी मूल्यवान संपत्ति है, और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके अधिकार का एक पहलू है। अनुदान जमानत जमानत आवेदन के अंतिम निपटान को लंबित एक व्यक्ति को अंतरिम जमानत देने के लिए संबंधित अदालत में अंतर्निहित शक्ति है। बेशक, यह अंतरिम जमानत देने के लिए संबंधित अदालत के विवेक में है या नहीं, लेकिन सत्ता निश्चित रूप से है। "

(५५) इसलिए, जहां भी जरूरत महसूस की जाती है, वहां एनडीपी मामलों से निपटने वाले एक विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी और जहां इस मामले को अनावश्यक रूप से देरी की जा रही है, वह एफएसएल रिपोर्ट की प्राप्ति तक अंतरिम जमानत दे सकती है और उसके बाद प्राप्त होने के बाद मामले पर विचार किया जा सकता है प्रतिवेदन।

(५६) उपरोक्त के परिणामस्वरूप, यह देखा जा सकता है कि:-

(i) निर्मित ड्रग्स वे दवाएं हैं जिन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2 (xi) में परिभाषित किया गया है और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। एनडीपीएस अधिनियम और एनडीपीएस नियमों के उल्लंघन में इस तरह की दवाओं का कब्जा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत अपराधी के आपराधिक अभियोजन को लागू करेगा।

(ii) केवल तथ्य यह है कि ड्रग्स जो एनडीपीएस अधिनियम और एनडीपीएस नियमों और साइकोट्रोपिक पदार्थों के तहत निर्मित दवाओं के तहत कवर किए जाते हैं, जैसा कि एनडीपीएस अधिनियम और एनडीपीएस नियमों के

अनुसूची / की अनुसूची में उल्लेख किया गया है और डी एंड सी द्वारा भी कवर किया गया है। अधिनियम और 1945 के नियमों का मतलब यह नहीं होगा कि अपराधी को केवल डी एंड सी अधिनियम और 1945 के नियमों के तहत दंडित किया जा सकता है

और एनडीपीएस अधिनियम और एनडीपीएस नियमों के खिलाफ आगे नहीं बढ़े। यदि एनडीपीएस अधिनियम और एनडीपीएस नियमों का एक उल्लंघन होता है, तो बाद के कड़े प्रावधानों का सहारा लिया जा सकता है।

(iii) एनडीपीएस अधिनियम और एनडीपीएस नियमों के संदर्भ में निर्मित ड्रग्स रखने वाला व्यक्ति डी एंड सी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिक्री, खरीद, परिवहन, वहन, भंडारण, वितरण आदि से संबंधित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना है और 1945 के नियम पंजाब एनडीपीएस नियम 2012 के प्रावधानों के रूप में भी।

(v) प्रत्येक मामले में यह पता लगाया जाना है कि क्या निर्मित दवा, जिसका उल्लंघन एक व्यक्ति द्वारा आरोपित किया गया है, 14.11.1985 और बाद में अधिसूचना दिनांक द्वारा दवा के लिए प्रदान की गई खुराक के प्रतिशत की अनुमेय सीमा के भीतर आता है। 29.01.1993 धारा 2 (xi) (बी) एनडीपीएस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई शक्ति के अभ्यास में जारी किया गया। हालांकि, निर्मित दवा के उल्लंघन या थोक में मात्रा के कब्जे को ध्यान में रखा जाना है और विशेष रूप से प्रति खुराक के अनुसार जब डी एंड सी अधिनियम और 1945 के नियमों का उल्लंघन होता है, जो कहना है कि उन्हें बेचा, खरीदा, वितरित किया गया है, संग्रहीत किया गया है, एक वैध लाइसेंस के बिना या एक वैध प्राधिकरण के बिना रखा गया, ले जाया गया। थोक में मात्रा का कब्जा एक संकेत होगा कि यह औषधीय या चिकित्सीय उपयोग के लिए नहीं है, लेकिन ड्रग के नशे की लत और ड्रग तस्करों द्वारा दुरुपयोग किए जाने की मांग की जाती है और किसी को भी या अधिक मादक दवा या साइकोट्रोपिक के लिए लागू होने के लिए लागू किया जाएगा। खुराक रूपों में उस विशेष दवा का पदार्थ न कि केवल इसकी शुद्ध दवा सामग्री।

(vi) जब एक निर्मित दवाओं को थोक रूप में बेचा, खरीदा, वितरित, संग्रहीत, परिवहन, ले जाया गया, किया जाता है, तो धारा 2 (VIIA) और (XXIIIA) के तहत शक्तियों के अभ्यास में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 18.11.2009 की अधिसूचना दिनांकित दिनांक। एनडीपीएस अधिनियम लागू होगा और यह सवाल है कि इन दवाओं में अधिसूचना के संदर्भ में एक अपवाद है दिनांक 14.11.1985 लागू नहीं होगा क्योंकि अपवाद लागू होंगे जब निर्मित दवाएं औषधीय या चिकित्सीय उपयोग के लिए होंगी।

(vii) निर्मित दवाओं की मात्रा को प्रति कैप्सूल के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाना है जब इन्हें उचित लाइसेंस या प्राधिकरण के बिना किया जाता है। दूसरे शब्दों में, एक कैप्सूल में निर्मित दवा की मात्रा खुराक पर विचार नहीं किया जाना है, लेकिन एक साथ कैप्सूल की संख्या में खुराक को यह निर्धारित करने के लिए विचार किया जाना है कि क्या अधिसूचना में प्रदान किए गए अपवाद 14.11.1985 मादक पदार्थ की घोषणा करते हैं। और तैयारी के रूप में उल्लेख किया गया दवाओं के लिए किया जाना है।

(viii) यह सुझाव दिया गया है कि राज्य अधिकारियों को ड्रग्स प्राप्त करना चाहिए, जिसके संबंध में एक उल्लंघन है और जिसे जल्द से जल्द रासायनिक विश्लेषकों द्वारा जांच की जाती है और जल्द से जल्द अपराधी को दी गई एक रिपोर्ट दी जा सकती है ताकि स्थिति हो सके। यह पता लगाया कि क्या कथित अपराधी दवा की अनुमेय मात्रा के कब्जे में था या अन्यथा। यदि यह देरी है तो यह अपराधी को कम से कम अंतरिम जमानत के लिए हकदार होगा जब तक कि रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती।

(ix) खोज और जब्ती के संबंध में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाना है। NCB द्वारा जारी किए गए निर्देश को परिचालित किया जाना चाहिए ताकि इन्हें दिशानिर्देशों के रूप में पालन किया जाए। दिशानिर्देशों का उल्लंघन अवैधता या

490I.L.R. पंजाब और हरियाणा 2015 (1)

अनियमितता के अनुसार नहीं होगा जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि न्याय की विफलता का सामना करना पड़ा है या परिणामस्वरूप पूर्वाग्रह में शामिल है।

(x) थाना सिंह बनाम के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों को निर्धारित किया गया और उसी का उल्लंघन आवश्यक रूप से दंडात्मक परिणामों सहित इसके परिणामों को पूरा करेगा।

(57) उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, संदर्भ का उत्तर दिया गया है। यह माना जाता है कि निर्मित दवाएं मादक दवाओं का हिस्सा हैं और एक व्यक्ति को उल्लंघन में और थोक मात्रा के कब्जे में पाया जाता है, जो ऐसा है कि इसका उपयोग चिकित्सीय या औषधीय उद्देश्यों के अलावा अन्य के लिए किया जाता है, लेकिन नशे के लिए या एक उत्तेजक प्रभाव प्राप्त करने के लिए या कब्जे में है दवाओं के संबंध में साइकोट्रोपिक पदार्थ जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, **1940** और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक नियमों के तहत एक उल्लेख पाते हैं, **1945** को एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोशिश की जा सकती है और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। जमानत आवेदन पर सवालों पर विचार किया गया है। इसलिए, यहां कुछ भी नहीं कहा गया है, मामले की योग्यता पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं लिया जाएगा और प्रत्येक मामले में सीखा ट्रायल कोर्ट के मामले को साक्ष्य और सामग्री के आधार पर विचार करेगा जैसा कि इससे पहले जोड़ा गया है। मामलों को निपटान के लिए सीखा एकल न्यायाधीश को वापस भेजा जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पारिंदर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

जींद, हरियाणा
